₹ 10

www.kewalsachtimes.com

अक्टूबर 2025

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी के रूपए कमाने की भूख ने किया

दवा उद्योग का बंटाधार

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

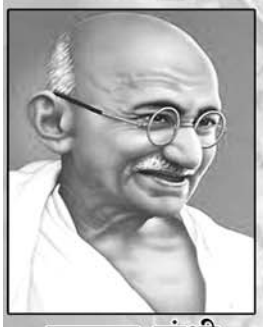

महात्मा गांधी
02 अक्टूबर 1869

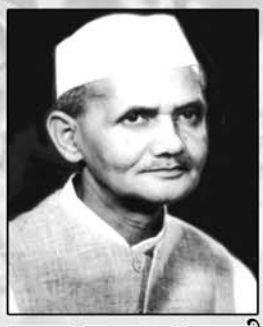

लाल बहादूर शास्त्री
02 अक्टूबर 1904

अभिजीत सावंत
07 अक्टूबर 1981

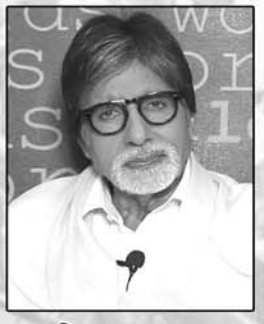

अमिताभ बच्चन
11 अक्टूबर 1942

गौतम गंभीर
14 अक्टूबर 1981

स्व०एपीजे कलाम
15 अक्टूबर 1931

नवीन पटनायक
16 अक्टूबर 1946

हेमा मालिनी
16 अक्टूबर 1948

अनिल कुंबले
17 अक्टूबर 1970

वृंदा करात
17 अक्टूबर 1947

सनी देवल
19 अक्टूबर 1956

नवजोत सिंह सिद्धू
20 अक्टूबर 1963

वीरेन्द्र सहवाग
20 अक्टूबर 1978

कादर खान
22 अक्टूबर 1932

परिनीति चोपड़ा
22 अक्टूबर 1988

सुनील भारती मित्तल
23 अक्टूबर 1957

प्रभाश राजू
23 अक्टूबर 1979

रवीना टंडन
26 अक्टूबर 1974

अनुराधा पौडवाल
27 अक्टूबर 1954

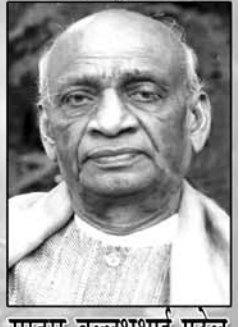

सरदार वल्लभभाई पटेल
31 अक्टूबर 1875

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

नमामि गंगे प्रोजेक्ट में

महालूट

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

''मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी''। भागीरथ की भागीरथी प्रयास ने धरती पर गंगा माँ को उतारा और तब से लेकर आज तक वह अविरल लोगों के पाप को धोती जा रही है। लोगों के अंतिम यात्रा भी माँ की गोद में ही होती है लेकिन कलियुग के लोगों ने पवित्र गंगा माँ को दूषित करने का कोई कार्य नहीं छोड़ती। कारखाना का दूषित पानी एवं शहरों की गंदगी भी नाले के द्वारा गंगा की स्वच्छ पानी में जाकर मिलकर उस पवित्र जल को दूषित कर रहा है। 2014 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार केन्द्र में बनी तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर काम करना शुरू कर दिये और गौ, गंगा और गायत्री पर कार्य प्रारंभ कर दिया। गंगा नदी की निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना बनाकर कार्य शुरू हुआ और कई प्रदेश के घाटों पर इसकी झलक दिखाई भी देने लगी साथ ही साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर होने की चर्चा भी। कैग की रिपोर्ट में वित्तिय अनियमितता की बात भी सामने आयी है। कई शहरों की सड़कों को खंडहर बना दिया गया है। अच्छी एवं करोड़ों रूपये की लागत से बनी सड़कों खोदकर आमजनता के टैक्स के पैसों का बंदरबाट हो रहा है और नागरिकों को असुविधा हो रही है वह अलग विषय बनता जा रहा है। कुछ खास-खास कंपनियों को वर्क देकर मोटी कमीशन की उगाही राजनेता एवं पदाधिकारी कर रहे हैं जिसकी वजह से आवाम की आवाज को दबा दिया जा रहा है।

दूषित जल मानव तो छोड़िए पशु-पक्षी भी ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। भारत देश धर्म के आधार पर चलता है और मानने के लिए संविधान है। देश की कई नदियों को माँ की उपाधि दी जाती है और उसमें गंगा नदी का अलग ही महत्व है। मर्यादा पूरूषोत्तम श्रीराम के पूर्वज भागीरथ ने हजारों वर्षों की तपस्या करके गंगा माँ को पृथ्वी पर उतारा और वह उस वक्त से लेकर आज तक अविरल मानव कुल को पापमुक्त बना रही है। **सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग** में गंगा नदी की कई कहानियां हैं जिसपर गर्व किया जाता रहा है लेकिन **कलियुग** में गंगा मईया दूसरे का पाप धोते-धोते खुद मैली होती जा रही है जिसकी वजह से 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी ने गंगा नदी में जाने वाले दूषित जल को स्वच्छ जल बनाने एवं नदी में गाद एवं अन्य प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसका पुनरूद्धार कराने के लिए जून 2014 में **नमामि गंगे प्रोजेक्ट** को शुरू किया और इसके लिए अलग से 26,824.86 करोड़ है। 2014-15 से 2024-2025 तक 23,424.86 करोड़ रूपये और तो और 2025-26 के लिए 34,00 करोड़ रूपये शामिल है। **नमामि गंगे प्रोजेक्ट** पर कई राज्यो में अपशिष्ट जल उपचार पर कार्य करने के लिए सीवेज के उपचार और प्रबंधन के लिए बुनियादी ढ़ाचे का विकास किया गया है साथ ही साथ घाटों एवं श्मशान घाटों का विकास किया गया है। इसको सफल बनाने के लिए रैलियों, अभियानों, प्रदर्शनियों, श्रमदान, स्वच्छता अभियान, प्रतियोगिताओं, वृक्षारोपण अभियानों और संसाधन सामग्री के विकास और वितरण के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई और व्यापक प्रचार के लिए टीवी/रेडियो, प्रिंट मीडिया विज्ञापन, फीचर्स लेख के साथ विज्ञापन की गयी। नदी के किनारे वनों का विकास का कार्य चल रहा है। नदी में मछली और अन्य जीवों के लिए पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार गंगा नदी के पुनरूद्धार के कार्य में लगी है तो दूसरी तरफ पदाधिकारी एवं ठेकेदार जमकर महालूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कैग ने भी इस मामले पर सवाल उठाया है। सड़कों का अतिक्रमण हो रहा है तथा जिस प्रकार सीवेज का निर्माण हो रहा है उसका भविष्य अल्पआयु होने के साथ-साथ किसी भी प्रकार का मापदंड का ख्याल नहीं रखा जा रहा है जिसका भौतिक सत्यापन करने पर स्पष्ट हो जाता है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम चल रहा है। फतुहा और फुलवारी शरीफ जैसे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) और इंटरसेप्शन और डायवर्सन नेटवर्क का किया गया है। अब इसका कितना लाभ हुआ है यह तो जनता समझ ही रही है। बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। कोरोना काल में भी इस परियोजना की सच्चाई सबके सामने आई थी। बिहार में काम कर रही है कंपनी की पड़ताल करने पर सारी सच्चाई सामने आ जायेगी। सत्ता पक्ष की तरह विपक्ष को भी सिर्फ कुर्सी हासिल करने के चक्कर में बिहार में चल रहे विकास कार्य की गुणवत्ता से कोई सारोकार नहीं रह गया है। सड़कों को बीच में, किनारे में, कहीं 03 फीट चौड़ा, 05 फीट गहरा तो कहीं 04 फीट गहरा, 04 फीट चौड़ा नाले का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है जिसकी वजह से स्थानीय जनता को घोर संकटों का सामना करना पड़ता है। स्थिति इतनी भयावह है की बहुत जगहों पर नाले को सही ढ़ंग से ढ़का भी नहीं गया है, वैसे में कौन कब हादसे का शिकार हो जायेगा कहना मुश्किल है। मोदी के सपने पर ग्रहण लगाने वाले संवेदक और उनके साथ गठजोड़ में शामिल संबंधित विभाग के अधिकारी सबकुछ जानते हुए मौनी बाबा बने हुए हैं वैसे में सरकार की महत्वकांक्षी नमामि गंगे परियोजना भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में फल-फूल रहा है। आज भी गंगा नदी की घाटों की स्थिति नारकीय है और कुछ प्रमुख शहरों को छोड़ दिया जाये तो घाट एवं श्मशान घाट भी अपनी बारी का बाट जोह रहा है। बुडको एवं नगर विकास के अधिकारी एवं इंजीनियर की लापरवाही की वजह से संवदेक किसी भी प्रकार का मापदंड का ख्याल नहीं रखते हुए सरकारी खजाना को खाली कर जनता की आंख में धूल झोकने का काम कर रहा है। अब यह चर्चा होने लगा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जन-जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की सफलता को सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है जिसके लिए धन की सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। गंगा नदी का पुनरूद्धार के आड़ में घाटों का सौन्दीयकरण और वृक्षारोपण सहित कई कार्यों में धांधली नजर आ रहा है। स्थानीय वार्ड पार्षद भी सबकुछ देखते हुए चुप बैठे है और शहरवासी विकास के नाम पर चुप हैं परन्तु दूसरी ओर सच्चाई यही है की नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सभी राज्यों की हालत लगभग एक ही जैसी है, खासकर यूपी, उत्तराखंड के साथ बिहार और झारखंड में आस्था भी जुड़ा हुआ है लेकिन गंगा नदी में गंदगी आज भी जा रहा है। एक ही काम को कई किस्तों में होने की वजह से सड़कों को कई बार खोदा गया है लेकिन कार्य को पूर्ण आज तक नहीं किया गया लेकिन सड़के खोदी जा रही है और बनाई जा रही हैं का दौर आज भी जारी है ताकि प्रोजेक्ट के नाम पर महालूट को अंजाम दिया जा सके।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्ष:- 15, अंक:- 172 माह:- अक्टूबर 2025 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

सितम्बर 2025

मनमानी

मिश्रा जी,

एक के बाद एक बीमारी और उसके ईलाज में देश की जनता की गाढ़ी कमाई पर दवा कंपनियां डाका डाल रही है और इन कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होने की वजह से दवा का दाम हो या अन्य विषय कंपनिया अपनी मनमानी कर रही हैं। सितम्बर 2025 अंक में प्रकाशित खबर ''**कानून के बावजूद दवा कंपनियों की मनमानी**'' में डॉक्टर एवं दवा कंपनी के बीच कानून रहने के बाद भी इसपर दवा कंपनिया मनमानी कर रही हैं। डॉक्टरों पर तो अंकुश लगाया जा सकता है लेकिन दवा कंपनिया 10 रूपये की दवा 100 रूपये में बेच सकती है। मजबूत खबर है।

● **संदीप कुशवाहा, टावर चौक, मुजफ्फरपुर**

अतिक्रमण

संपादक महोदय,

मैं आपकी पत्रिका का नियमित पाठक हूं और आपका संपादकीय आवाम की आवाज है जैसा है लिखने की वजह से इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। सितम्बर 2025 अंक में आपने संपादकीय में वर्त्तमान समय की सच्चाई ''**पदाधिकारियों के संरक्षण में अतिक्रमण**'' आलेख में मूलभूत कारणों का सटीक उदाहरण के साथ लिखा है। अतिक्रमण एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका सही समय पर ईलाज नहीं किया गया तो यह आमजनता के साथ प्रशासन के लिए भी नासूर बन जायेगा। उदाहरण के साथ समस्या और उसका समाधान को भी लिखा है। अतिक्रमण से अवैध कमाई भी हो रही है। अच्छी खबर।

● **अभिषेक मिश्र, बूटी मोड़, गाड़ीखाना, राँची**

अन्दर के पन्नों में

17

बदलाव

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका की खबरे सदैव जानकारीप्रद एवं जनहित के लिए होती हैं। केन्द्र सरकार की कानून व्यवस्था के तहत अर्थ-व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव की खबर को सितम्बर 2025 अंक में ''08 साल बाद GST में बड़ा बदलाव'' आमजनता के काफी राहत पहुंचाने वाला है। GST की वजह से गाड़ी खीरदने में लोगों को लाखों रूपये की बचत हुई है। दवा में GST में बदलाव की वजह से भी आवाम को काफी सहूलियत हो रही है। आमजनता का पैसा शिक्षा एवं चिकित्सा में समाप्त हो जाता है जैसा स्थिति अधिकांशत: घरों में देखने को मिलता है। जरूरत के वस्तुओं में GST के बदलाव से काफी राहत मिला है। बढ़िया खबर है।

● **मनोज साव, घंटा घर, भागलपुर, बिहार**

100 साल

संपादक महोदय,

सितम्बर 2025 अंक में संजय कुमार सिन्हा ने ''**आरएसएस के 100 साल**'' आलेख में एक संगठन के पूरे कार्य-कलाप को पूर्ण विस्तार से लिखा गया है। संघ ने राष्ट्र के विभिन्न विपदाओं में अपनी कर्मठता और त्याग एवं सेवा का परिचय देकर देश के भीतर राष्ट्रवाद का परचम फहराया और अपने संघ के भीतर सैकड़ों संगठन के माध्यम से सनातन संस्कृति को भी जिवंत रखने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी संघ ने देश के भीतर जन-जागरण का काम किया है। संजय कुमार सिन्हा ने अपने खबर में संघ के द्वारा जा रहे सभी कार्य को पूरी गंभीरता एवं प्राथमिका के साथ पाठकों के बीच रखा है जो काबिले तारिफ है। सटीक एवं उपयोगी खबर।

● **सोहन गुप्ता, नजफगढ़ बस स्टैण्ड चौक, दिल्ली**

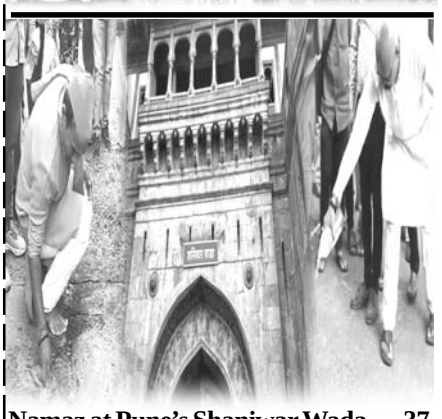

Namaz at Pune's Shaniwar Wada.....37

बिहार चुनाव

मिश्रा जी,

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसकी राजनीतिक खबरों को अवश्य कर पढ़ता हूं। सितम्बर 2025 अंक में अवधेश कुमार की खबर ''**कई साफ संकेत दे रहे हैं बिहार के चुनाव**'' में बिहार की वर्त्तमान समय की समस्या और वोटरों के बीच चल रही SIR की बात ने विपक्ष के लिए एक मुद्दा दे दिया है। आपकी पत्रिका की यह खबर वास्तव में बिहार के पाठको के लिए वरदान है और वोट के महत्व को समझने में कामयाब हो सकते हैं। 15 साल बनाम 20 साल की राजनीति को समझने का सटीक खबर को प्रकाशित किया गया है। दूसरी खबर ''सी.पी राधाकृष्ण बने भारत के 15वें उप राष्ट्रपति'' भी अच्छी लगी।

● **संजय पासवान, मानपुर बाजार, गया**

नेपाल

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका का सभी अंक पठनीय है. अमित कुमार की सितम्बर 2025 अंक में प्रकाशित खबर ''**नेपाल में तख्तापलट**'' में सोशल मीडिया से सड़कों तक विद्रोह की पूरी घटना को विस्तार से लिखा है। जिस प्रकार नेपाल की घटना हुई वह बड़ी चिंतनीय एवं निंदनीय है लेकिन जब सरकार उदासीन हो जाती है तो जनता कानून अपने हांथ में ले लेती है। आम नेपाली की बढ़ती बेरोजगारी सहित आर्थिक निराशा की वजह से एक बड़ी घटना को पूरे विश्व ने देखा। पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी की वजह से हिंसा और भड़क गई और नेपाल के इतिहास में यह काला अध्याय लिखा गया। अमित कुमार ने सटीक विश्लेषण इस खबर में किया है जो सराहनीय है।

● **अभिषेक कुमार मिश्र, सीतामढ़ी बाजार, सीतामढ़ी**

38

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

भारत में दवा नियामक व्यवस्था पर गहराते सवाल

डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी के रूपए कमाने की भूख ने किया दवा उद्योग का बंटाधार

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

भारत का दवा उद्योग अभी करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का साधन है, लेकिन DCGI डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी के रुपए कमाने की भूख दवा उद्योग बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में COLDRIF कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई हो गई, इसका एकमात्र कारण DCGI डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी हैं। कफ सिरप में DIETHYLENE GLYCOL और ETHYLENE GLYCOL की मात्रा अधिक रहने और आईपी में इसकी मात्रा अधिक होने से बच्चों की मौत हुई है। आनन-फानन में 10/10/2025 को आईपी में संशोधन कर कहा गया है कि कफ सिरप में इसकी मात्रा 0.10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब रघुवंशी इंडियन फार्माकोपोयिया कमिशन के प्रमुख थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया और अभी लगातार इतने वर्षों से डीसीजीआई के पद पर हैं तो उन्होंने इंडियन फार्माकोपिया कमिशन को इसके लिए क्यों नहीं कहा, यह बात सवालों के घेरे में है? COLDRIF कफ सीरप बनाने वाली कंपनी SRESAN फार्मा तमिलनाडु की दवा कंपनी है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 6 सालों से तमिलनाडु के दवा कंपनियों का भारत सरकार डीसीजीआई (CDSCO) द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। निरीक्षण हो भी क्यों; श्री राजीव रघुवंशी को हिमाचल और उत्तराखंड के दवा कंपनियों से वसूली से फुर्सत मिले तब ना। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों पर रिस्क बेस इंस्पेक्शन (RBI) होता रहता है और कंपनियों को जहां से राजीव रघुवंशी को पैसा नहीं मिलता है बेवजह बंद किया जाता है। श्री राजीव रघुवंशी के बार-बार सेवा निवृत्ति के बाद एक्सटेंशन से आहत होकर डॉक्टर डी मुथु ने मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरई बेंच में याचिका लगाई, जिसका केस नंबर-W.P. (MD) No.-6882/2025 है। कोर्ट ने याचिका स्वीकृत करते हुए भारत सरकार को नोटिस जारी किया है। राजीव रघुवंशी और उनकी पत्नी पूनम रघुवंशी को कमाने की भूख इस कदर लगी हुई है कि यह लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। राजीव रघुवंशी अपना काला धन पूनम रघुवंशी के कंपनी में लगाए जा रहे हैं। साथ ही कई फार्मा कंपनियों का पैसा भी पूनम रघुवंशी के कंपनी में अवैध रूप से लगा हुआ है।

भारत की औषधि नियामक प्रणाली एक बार फिर विवादों के घेरे में है। जबसे डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने औषधि नियंत्रक महानियंत्रक (DCGI)

का पदभार संभाला है, फार्मा उद्योग में कई गंभीर आरोप और अनियमितताओं की चर्चाएँ तेज हुई हैं। नीचे प्रस्तुत रिपोर्ट इन मुद्दों की पड़ताल करती है, जो उद्योग जगत में गूंज रही हैं।

जबसे श्री राजीव रघुवंशी ने वर्ष 2022 में भारत के औषधि नियंत्रक महानियंत्रक (DCGI) का पदभार ग्रहण किया है, तब से दवा उद्योग अत्यधिक बुरी स्थिति में पहुँच गया है, कुछ अपवादों को छोड़कर। चीन से भारी मात्रा में सस्ते और अवैध फार्मा API पदार्थ भारत में CDSCO के बंदरगाह कार्यालयों के माध्यम से कल्पना से परे तस्करी किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय API उद्योग बर्बाद हो रहा है। वर्तमान DCGI श्री राजीव रघुवंशी सीधे-सीधे इस पूरे मामले में शामिल हैं। MSME उद्योग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) अत्यधिक पीड़ा में है और बंद होने की कगार पर पहुँच चुका है। इस व्यक्ति ने अकेले ही भारतीय API उद्योग को उस स्तर तक नुकसान पहुँचाया है जितना कोई अन्य नहीं कर सका। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ डुअल यूज लाइसेंस (Dual Use Licenses) का दुरुपयोग उनके निर्देश पर विभिन्न जोनों द्वारा किया गया और माल को बंदरगाहों से पास किया गया तथा भुगतान डॉ. राजीव रघुवंशी, DCGI द्वारा प्राप्त किया गया। श्री राजीव रघुवंशी फार्मा उद्योग में सभी अवैध आयातों के सरगना (kingpin) हैं। यह व्यक्ति, डॉ. राजीव रघुवंशी ने वास्तव में देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को बेच दिया है। वह WHO के साथ मिलीभगत में हैं ताकि भारत के MSME यूनिट्स को बंद किया जा सके और भारतीय जनता को बड़ी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के हवाले कर दिया जाए ताकि वे ऊँचे दामों पर जनता को लूट सकें। Risk Based Inspection (जोखिम- आधारित निरीक्षण) शुरू कर उन्होंने अनेक छोटे-छोटे यूनिट्स को बंद करवा दिया है, जबकि बड़ी दवा कंपनियों के विरुद्ध, जिनके खिलाफ सरकार की केंद्रीय और राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा बड़ी संख्या में NSQ (Not of Standard Quality) रिपोर्ट जारी की गई हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। वे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। चूँकि वे पहले निजी क्षेत्र में ऐसी ही कंपनियों में काम कर चुके हैं, इसलिए अब वे उन्हीं कंपनियों से धन प्राप्त कर रहे हैं ताकि छोटी फार्मा इकाइयों को बंद कर उनकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकें। वर्तमान में MSME यूनिट्स सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएँ बनाकर भारतीय जनता को राहत देती हैं और निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। यदि स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। श्री राजीव रघुवंशी ने भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बेच रहे हैं। हाल ही तक डॉ. राजीव रघुवंशी के पास Indian Pharmacopoeial Commission (IPC), गाजियाबाद का सेक्रेटरी-कम-वैज्ञानिक निदेशक (Secretary-cum-Scientific Director) का अतिरिक्त प्रभार भी था। सूत्रों के अनुसार उन्होंने फरवरी 2022 में इस पद से त्यागपत्र दिया था, जिसके बाद इस पद के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया। परंतु आश्चर्यजनक रूप से उन्हें पुनः उसी पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया और वे अगले 22 महीनों तक इस महत्वपूर्ण पद पर बने रहे। उन्होंने हर

भारतीय भेषज संहिता आयोग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
सैक्टर - २३, राज नगर,
गाज़ियाबाद - २०१ ००२, उत्तर प्रदेश, भारत

IPC

INDIAN PHARMACOPOEIA COMMISSION
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
Sector - 23, Raj Nagar
Ghaziabad-201 002 (U.P.), INDIA

डा. वी. कलईसैलवण
सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक

Dr. V. Kalaiselvan
Secretary-cum-Scientific Director

F. No. T.11015/01/2020-AR&D

Date: October 10, 2025

Subject: Amendment List 09 to IP 2022

The 9th Edition of Indian Pharmacopoeia (IP) 2022 has become effective from 1st December, 2022. Based on the scientific inputs, some monographs of the IP 2022 need amendments for their effective implementation. Accordingly, Amendment List 09 to IP 2022 is being issued containing such amendments and this shall become official with immediate effect.

All concerned are requested to bring it to the notice of all authorities under their control for compliance with the IP 2022.

(Dr. V. Kalaiselvan)

Encl. Amendment List 09 to IP 2022

To,
1. The Drugs Controller General (India)
2. All State Drug Controllers
3. CDSCO Zonal Offices
4. Members of the Scientific Body of the IPC
5. Directors of the Drugs Testing Laboratories
6. IDMA/OPPI/BDMA/FOPE/FSSAI/Small Scale Industry Associations

INDIAN PHARMACOPOEIA (IP) *Official Book of Drug Standards in India*
IP REFERENCE SUBSTANCES (IPRS) AND IMPURITIES *Official Physical Standards for Assessing the Quality of Drugs*
NATIONAL FORMULARY OF INDIA (NFI) *Reference Book to Promote Rational Use of Generic Medicines*
PHARMACOVIGILANCE PROGRAMME OF INDIA (PvPI) WHO Collaborating Centre for Pharmacovigilance in Public Health Programmes and Regulatory Services

Tel No: +91-120-2783392, 2783400, 2800401 E-mail: lab.ipc@gov.in Website: www.ipc.gov.in

AMENDMENT LIST-09 TO IP 2022

Oral Liquids Page 1335

Tests

Insert before **Uniformity of content**

Diethylene glycol and Ethylene glycol. Determine by gas chromatography (2.4.13).
Not more than 0.10 per cent, each of, Diethylene glycol and Ethylene glycol.

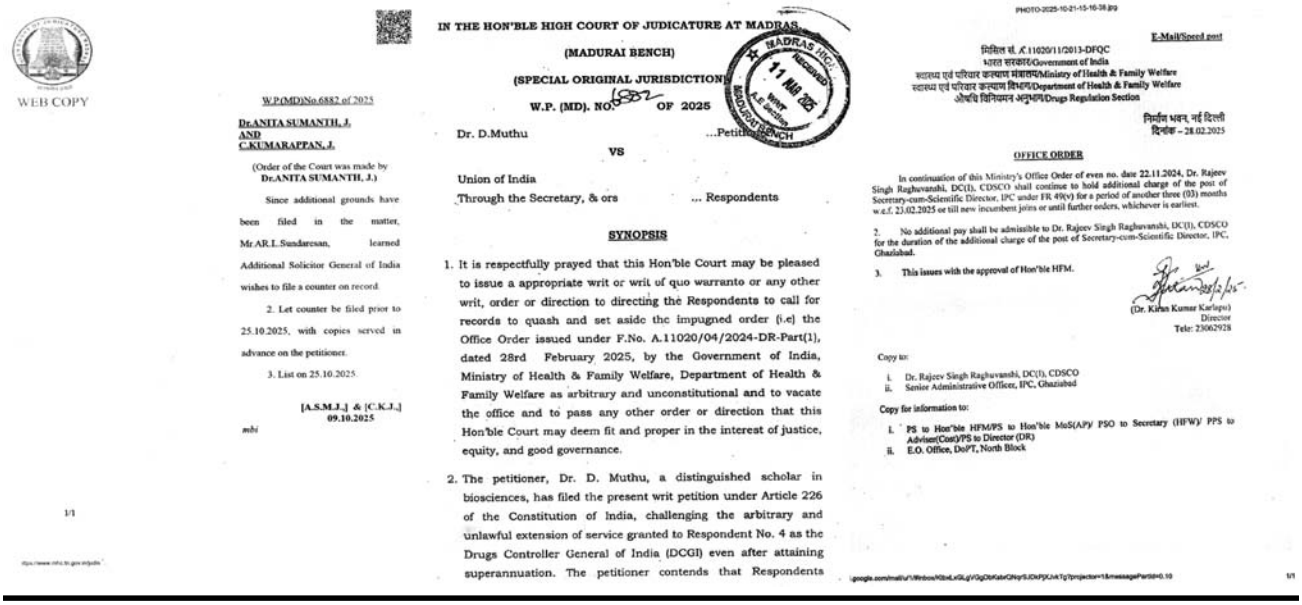

WEB COPY

W.P.(MD)No.6882 of 2025

Dr.ANITA SUMANTH, J.
AND
C.KUMARAPPAN, J.

(Order of the Court was made by
Dr.ANITA SUMANTH, J.)

Since additional grounds have been filed in the matter, Mr.AR.L.Sundaresan, learned Additional Solicitor General of India wishes to file a counter on record.

2. Let counter be filed prior to 25.10.2025, with copies served in advance on the petitioner.

3. List on 25.10.2025.

[A.S.M.J.,] & [C.K.J.,]
09.10.2025

mbi

1/1

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS

(MADURAI BENCH)

(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

W.P. (MD). NO. 6882 OF 2025

Dr. D.Muthu ...Petitioner

VS

Union of India
Through the Secretary, & ors ... Respondents

SYNOPSIS

1. It is respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to issue a appropriate writ or writ of quo warranto or any other writ, order or direction to directing the Respondents to call for records to quash and set aside the impugned order (i.e) the Office Order issued under F.No. A.11020/04/2024-DR-Part(1), dated 28rd February 2025, by the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare as arbitrary and unconstitutional and to vacate the office and to pass any other order or direction that this Hon'ble Court may deem fit and proper in the interest of justice, equity, and good governance.

2. The petitioner, Dr. D. Muthu, a distinguished scholar in biosciences, has filed the present writ petition under Article 226 of the Constitution of India, challenging the arbitrary and unlawful extension of service granted to Respondent No. 4 as the Drugs Controller General of India (DCGI) even after attaining superannuation. The petitioner contends that Respondents

PHOTO-2025-10-21-15-16-38.jpg

E-Mail/Speed post

मिसिल सं. A.11020/11/2013-DFQC
भारत सरकार/Government of India
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/Ministry of Health & Family Welfare
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/Department of Health & Family Welfare
औषधि विनियमन अनुभाग/Drugs Regulation Section

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक – 28.02.2025

OFFICE ORDER

In continuation of this Ministry's Office Order of even no. date 22.11.2024, Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi, DC(I), CDSCO shall continue to hold additional charge of the post of Secretary-cum-Scientific Director, IPC under FR 49(v) for a period of another three (03) months w.e.f. 23.02.2025 or till new incumbent joins or until further orders, whichever is earliest.

2. No additional pay shall be admissible to Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi, DC(I), CDSCO for the duration of the additional charge of the post of Secretary-cum-Scientific Director, IPC, Ghaziabad.

3. This issues with the approval of Hon'ble HFM.

(Dr. Kiran Kumar Karlapu)
Director
Tele: 23062928

Copy to:

i. Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi, DC(I), CDSCO
ii. Senior Administrative Officer, IPC, Ghaziabad

Copy for information to:

i. PS to Hon'ble HFM/PS to Hon'ble MoS(AP)/ PSO to Secretary (HFW)/ PPS to Adviser(Cost)/PS to Director (DR)
ii. E.O. Office, DoPT, North Block

1/1

संभव प्रयास किया कि इस पद पर नई भर्ती न हो, जिसके परिणामस्वरूप IPC के अनेक सक्षम अधिकारियों के करियर बर्बाद हो गए। यह सब कुछ उन्होंने मंत्रालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से किया, जो IPC की गाड़ियों और संसाधनों का दुरुपयोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए करते हैं। उनके प्रभाव में कई अवैध भर्तियाँ IPC में की गई। इसलिए मंत्रालय ने भी नई नियुक्ति प्रक्रिया रोक रखी है, ताकि उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों को कानूनी जांच से बचाया जा सके। सरकारी अधिकारी, जो IPC की फाइलों से संबंधित कार्य देखते हैं, वे सब डॉ. राजीव रघुवंशी के साथ मिलीभगत में हैं। उन्होंने बाहरी व्यक्तियों को IPC में नियुक्त कर वहाँ कार्यरत कर्मचारियों का उत्साह और मनोबल तोड़ दिया है। मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के पुत्र, पुत्रियाँ और रिश्तेदारों को अवैध रूप से IPC में नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों और नियुक्त व्यक्तियों के नामसरल जाँच से सामने लाए जा सकते हैं। डॉ. रघुवंशी को घटनाओं और छवि प्रबंधन (event-perception management) में अधिक विश्वास है। उनके द्वारा किया गया शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार अब चौंकाने वाले स्तर (astonishing level) पर पहुँच चुका है। मंत्रालय की लंबे समय से निष्क्रियता, विभिन्न हितधारकों (व्यक्तिगत या समूहों) द्वारा दर्ज कराई गई। कई शिकायतों के बावजूद यह दर्शाती है कि कुछ अधिकारी स्वयं भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पहले भी उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग, IPC में अपने लोगों की नियुक्ति और मंत्रालय व DOPT के भर्ती नियमों की अवहेलना से संबंधित कई शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने SSO (Senior Scientific Officer) की अल्पावधि अनुबंध नियुक्ति सभी सरकारी नियमों (DOPT और IPC भर्ती उपनियमों) की अनदेखी करते हुए की, जिससे योग्य और पात्र उम्मीदवारों की पूर्ण अनदेखी हुई। उनके कार्यकाल में हुई सभी नियुक्तियाँ किसी भी प्रकार से सरकारी मानकों, पात्रता या नियमों पर खरी नहीं उतरतीं। यदि इन पर गहन जाँच (thorough enquiry) की जाए, तो यह स्पष्ट रूप से एक बड़ा भर्ती घोटाला (major recruitment scam) सिद्ध होगा। डॉ. राजीव रघुवंशी का मंत्रालय में सहायक और सहयोगी श्री किरण कुमार कारलापू, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय में निदेशक हैं, उनके निर्देश पर डॉ. रघुवंशी ने कई ऐसी कंपनियों की फाइलें अनुचित रूप से पास कीं, जो दोनों के करीबी संबंधों में थीं। उन्होंने DCGI से करोड़ों रुपये की रिश्वत लेकर उन फाइलों को मंजूरी दी। इसके बदले में, किरण कुमार कारलापू ने उनके विरुद्ध दर्ज सभी शिकायतों को दबाया या कमजोर किया। ऊपर उल्लिखित सभी तथ्य आसानी से सत्यापित किए जा सकते हैं और पहले से ही उद्योग जगत और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित हैं। मामला केवल MSME इकाइयों के उत्पीड़न या बंद होने का नहीं है, बल्कि यह भेदभाव (Discrimination) का भी उदाहरण है। जो बड़े और प्रभावशाली लोग हैं, जिनकी "सेटिंग" है, उन्हें पूरी तरह से मुक्त छोड़ दिया जाता है, जबकि जिनका कोई संपर्क नहीं है या जिनके विरुद्ध किसी उच्चाधिकारी की नाराजगी है या जिनके खिलाफ बड़े कॉर्पोरेट लोगों द्वारा निर्देश दिया गया है, उन्हें शाब्दिक रूप से कुचल दिया जा रहा है। जो भी प्रभावशाली फार्मा उद्योग के बड़े लोग मंत्रालय, DCGI या मीडिया में कुछ कहते हैं, वे बस उनके पैर चाटते हैं (licking his feet) ताकि उनकी फाइलें जल्दी मंजूर हो जाएँ या वे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में अपनी छवि चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह सब मात्र स्वार्थ, हेराफेरी, भेदभाव और अधिकारों के दुरुपयोग का उदाहरण है। Twitter, LinkedIn, Facebook आदि पर भी MSME इकाइयों की आवाज नहीं उठाई जाती। बड़ी MNC कंपनियाँ हमेशा अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की चापलूसी करती रहती हैं ताकि वे सुर्खियों में रहें। जो लोग वहाँ लेख लिखते हैं, यदि उनके कंपनी के रिकॉर्ड, फाइलें या नियामक अनुमोदनों के लिए तैयार किए गए दस्तावेज देखा जाएँ, तो पता चलेगा कि वे सब जाली नैदानिक परीक्षण (bogus clinical trials), नकली स्थायित्व रिपोर्ट, सस्ती चीनी API और अमान्य पैकिंग सामग्री का उपयोग करते हैं, फिर भी वे बड़ी कंपनियाँ होने के कारण बेहतर मानी जाती हैं। सिर्फ इसलिए

किरण कुमार कारलापू

कि MSME इकाइयाँ इन बड़ी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा देती हैं और उनके दामों को जमीन पर लाने के लिए बाध्य करती हैं। वे MSME इकाइयों के बंद होने का समर्थन कर रहे हैं और यह सब "गुणवत्ता" के नाम पर किया जा रहा है। MSME इकाइयाँ ही उन्हें सिखा रही हैं कि किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ कैसे बनती हैं। यदि इन्हीं तथाकथित बड़ी कंपनियों के डेटा इंटीग्रिटी (data integrity) की जाँच की जाए, तो वे भी वही दोषी पाई जाएँगी, अन्यथा US FDA और यूरोपीय एजेंसियों ने उन्हें Import Alert (आयात प्रतिबंध) क्यों लगाया होता? मामला पूरी तरह भेदभाव, हेराफेरी और भ्रष्टाचार का है, जो केवल MSME को निशाना बनाता है ताकि कुछ चुने हुए समूहों को दिखावा करने के लिए बलिदान बनाया जा सके। यदि रिकॉर्ड मांगे जाएँ, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि नियामक अनुमोदनों (Regulatory Approvals) और कार्रवाईयों (Actions) में MSME और बड़ी कंपनियों के बीच भारी भेदभाव और भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि लंबित आवेदनों (pendency) के मामलों में भी स्थिति गंभीर है। DCGI कार्यालय (CDSCO) में क्लिनिकल ट्रायल, Written Confirmation, New Drug Approvals, RDNA Approvals, Medical Devices, IVD Applications, Ethics Committee Approvals और हजारों Post&Approval Changes Applications लंबित पड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर के कार्य राज्य जैसी मानसिकता से नहीं चल सकते। इस कारण उद्योग अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों और विश्वसनीयता को खो रहा है। कई मामलों में केवल चुनी हुई कंपनियों का काम किया जा रहा है। जो बड़ी रिश्वतें (donations) देती हैं, जबकि बाकी को "First Come First Serve" के आधार पर निपटाने के बजाय जानबूझकर देरी की जाती है। DCGI के निर्देश पर, जानबूझकर अनावश्यक आपत्तियाँ (queries) दी जाती हैं ताकि अनुमोदन में विलंब हो। यह सब भारी भ्रष्टाचार और पक्षपात के तहत हो रहा है। उनका करीबी साथी, श्री दिलीप राजपूत (Director–Admin), उनकी ओर से रिश्वत लेकर अधिकारियों के तबादले करता है।

पिछले वर्ष, चेन्नई बंदरगाह और हवाई अड्डे पर दो Deputy Drug Controllers (DDCs) की नियुक्ति की गई, हालाँकि इन पदों पर केवल Assistant Drug Controllers (ADCs) को नियुक्त किया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर एक Deputy Drug Controller श्री अजय सचन, जो वर्तमान में उत्तर जोन में तैनात हैं, हमेशा अपनी मनचाही पोस्टिंग पाते हैं। श्री दिलीप राजपूत पूरी तरह CDSCO और DOPT की ट्रांसफर नीति की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे अधिकारियों में भारी असंतोष और आक्रोश फैल गया है। यह स्पष्ट करता है कि वे कुछ व्यक्तियों का पक्षपातपूर्वक समर्थन कर रहे हैं। इसी प्रकार, एक अन्य Deputy Drug Controller डॉ. विनोद कुमार, जो पहले Import - Registration Division में थे, उन्होंने श्री दिलीप राजपूत के साथ सौदा तय कर फिर से Subsequent New Drugs Division हासिल कर लिया। ये लोग मंत्री जे.पी. नड्डा के नाम पर रिश्वत लेते हैं और उसका एक हिस्सा DCGI को देते हैं। CDSCO के

To

Ms. Punya Salila Srivastava,
Secretary, Department of Health & Family Welfare,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110011

Dated 7th February, 2025

Subject: Revelation of correct facts against the false and misleading claims on the so-called achievements of Dr.Rajeev Singh Raghuvanshi, DCGI, CDSCO– submission regarding

Madam,

I am a duty conscious citizen of this country and have been exposing the corrupt activities of the officials placed in key senior posts of the Government. My objective is not to embarrass but to bring to the notice of the concerned authorities for their information in order to take corrective measures in time by way of making a thorough probe into the verifiable facts stated in my complaint. If no corrective action is taken, it is presumed that the corrupt activities of the said official was going on either because of the ignorance of the said authority or with the tacit approval/blessings of the said authority/authorities for the reasons best known to each of them, forcing me then to bring the contents of my complaint to the notice of the press for public scrutiny.

Dr. Rajeev Sigh Raghuvanshi, the current DCGI (till his superannuation on 28th February,2025) is from the phama industry having corporate culture of working in the system where success is claimed by the CEO and failure is passed on to the subordinates. Since he had already worked in pharma companies like Dr.Raddy's Lab, Ranbuxy etc., he is already well-acquainted with the vices of corporate culture of appeasing various drug regulatory authorities in order to serve the vested interests of the company where he was working. Now having been posted in the top post of regulatory body of CDSCO, Dr. Raghuvanshi has been exploiting the advantage position of his post, plundering the system to

the worst performance of CDSCO under the leadership of Dr.Rajeev Singh Raghuvanshi precisely because of lack of team work. Dr.Raghuvanshi was literally touching the feet of WHO team leader Mr. Ali Raja and also begged all members of WHO team to give ML 3 for CDSCO. He continuously begged for ML 3 for about 4 hrs on 19th September and another 4 hrs on 20th September. Dr.Raghuvanshi personally called Mr. Ali into his room and almost touched his feet to give ML 3. In this way Dr. Raghuvanshi spoiled image of CDSCO, and that of India as well by bowing before WHO team for ML 3. It had never happened in the history of CDSCO. This fact may be verified by the Ministry from anyone who was part of NRA assessment. He knew that if CDSCO got ML 2, it would pose threat to his chair and also it would badly affect during ICDRA event held in October 2024. Tragedy was that nobody from the Ministry ever checked all the wrong and misleading facts about the false information provided by Dr. Raghuvanshi to the Ministry about the outcome of NRA assessment. He also requested Mr. Ali to praise him during meeting with Secretary Madam.

Dr. Raghuvanshi's performance can also be seen from the outcomes of the NRA assessment. In September 2024 assessment, CDSCO got ML 4 only in 3 Indicators and ML 3 in 6 indicators as against ML 4 in 5 indicators and ML 3 in 4 indicators during 2017 assessment. In this way he badly damaged the image of CDSCO during NRA assessment. Unfortunately the Ministry is not aware about any fact about this as everybody relied on what Dr. Raghuvanshi falsely made them to believe his tall and false claims.

3. ICDRA—claiming it grand success because of him based on wrong and misleading facts by Dr. Raghuvanshi :

Facts Check:
It was decided to host 19th ICDRA by the CDSCO in 2016 and for which WHO also consented CDSCO request in the 17th ICDRA held at Cape Town, South Africa in 2016. The 19th ICDRA event was supposed to be held in October 2020 as per the schedule, but was postponed due to COVID-19 outbreak. Health Ministry and CDSCO had detailed discussions with WHO about the venue, program and budget in 2021. Accordingly, Ministry sanctioned Rs 10 crore for this event in 2021. Venue and all other details were finalised in the year 2022. It means, all the base work was done much before Dr.Raghuvanshi took over the charge of DCGI in February 2023.

regulatory experience and no practical knowledge of inspections and enforcement. They have respected him mainly because of authority of JS Patnaik Madam, as the entire exercise was under taken under her direct control and supervision in the RBI. As Dr.Raghuvanshi claimed to have improvement in quality culture and infrastructure in the MSME sector due to RBI, it is big false claim. Still the percentage of NSQ remained same in the country. The MSME units whose license were cancelled during RBI, the same units were restarted after 3-6 months but producing the same low quality of the product. Of late the dark side of the present arbitrary, non-transparent current RBI system has led to major corrupt practices in the CDSCO under the very direction of none but Dr. Raghuvanshi at all levels by of exploiting the firms by blatant misuse of the RBI.

Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi fooled the public, media and the Ministry by giving all false claims about RBI. As already stated, he has not initiated the concept of RBI in CDSCO. In true sense, in his tenure, corruption was rampant in CDSCO because of blatant misuse of RBI. These facts may be checked/verified by the Ministry by enquiring with any industry representatives. Unfortunately, the very post of DCGI is the only single point of contact for the Ministry in the present situation. Earlier times, Ministry was contacting multiple people from the CDSCO and industry for the feedback. Hope, the days may change again for better responsible, transparent RBI system after the exit of Dr. Raghuvanshi from the scene.

2. NRA Assessment—False and misleading facts, spread by Dr. Raghuvanshi :

Dr.Singh is said to have claimed that CDSCO has been declared as Functional NRA by the WHO with Maturity Level (ML) 3 in October 2024 because of "his contribution and efforts". Out of 9 Indicators, only in 3 Indicators got ML 4 and 6 Indicators got ML 3. It was rather the worst performance of CDSCO in the NRA assessment in comparison to the performance of CDSCO in all previous years.

Fact Check, what Dr. Raghuvanshi supressed and misled:

CDSCO has been declared as Functional NRA by WHO since 2000 and it had undergone successful multiple audits in the subsequent years, 2004, 2007, 2009, 2012 and 2017 by WHO. CDSCO performed very well in all times.

Truth about the assessment in 2024:

It was true that WHO has given ML 2 for CDSCO after the assessment during the pre-exit meeting on 19th September 2024. But it was in fact

the best of his ability by way of holding an iron hand against his subordinates so that none could dare to challenge the arbitrary and autocratic way of his functioning on the one hand, and appeasing his masters sitting in the Ministry, on the other by way of creating a false image of his capabilities and misleading achievements. Dr.Rajeev made multiple tall claims/achievements at various forum, even with the Ministry, officials on various topics. Here I am providing you the correct facts about his so-called achievements, demolishing his claims:-

1. **Risk Based Inspections (RBI)— His false and misleading claims:**

Dr.Singh made tall claims that the system of RBI was introduced by him for the 1st time in the history of CDSCO. As per his individual initiative around 700 firms were inspected. As a result licenses of many firms were either cancelled or suspended and stringent action taken on MSME units. He further claims that introduction of this RBIs improved quality culture and infrastructure. Non-serious players are out the business.

Fact Check:

This is for your kind information that the concept of RBI was introduced for the 1st time in CDSCO on 23-05-2016, much before he took over DCGI post. Earlier inspections were conducted in a very transparent manner by constituting a team of 6 officers headed by an ADC and one expert from the labs. Detailed check list was developed for inspections. Inspectors are from outside the concerned State. More than 300 firms were inspected that time, about 100 licenses were cancelled or suspended for the manufacturing activities.

Truth:

Truth is that when the notorious issue of cough syrup issue in Africa was flashing headlines of the press, the then HFM directed for restarting RBI inspections as the same was discontinued by Dr. Singh's predecessor, Dr. Somani for the reasons best known to him. It was meticulously implemented under the direct supervision of the then JS Ms Aaradhana Patnaik Madam, who engaged Dr Raghuvanshi for the task. She visited all Zonal offices of CDSCO and had detailed deliberations with all concerned State Licensing authorities (SLA) to take strong action against violators. She monitored the outcomes of inspections continuously through VC and physical meetings. In fact, no SLA has any respect or recognition to the authority of Dr. Raghuvanshi, for the glaring reasons of his lack of

Verified Truth:

Dr.Rajeev Raghuvanshi did not bring the event of the 19th ICDRA to India, as he falsely claimed. His role in organising ICDRA event was nothing but a big ZERO. All work related to this event i.e. selection of venue, program schedule, food, cultural program etc were already done much before he joined CDSCO. He just managed stage show as he happened to be there. It was just by streak of his luck that the event happened in his tenure, which was originally scheduled in 2020. Again regrettably, Ministry without making a fact check believed what Dr Raghuvanshi made them to believe his fiction.

4. Other false and unverified claims of Dr. Raghuvanshi's achievements:

1. **Digitization:** Dr.Raghuvanshi claims majority of the regulatory process are converted to digital mode like Blood bank licenses, PAC etc. In fact, all these were already in the pipeline much before he joined in CDSCO. The concept of mega digitization of CDSCO work was recommended in the Chintan Shivir held in Feb 2023, i.e. before he joined CDSCO.
2. **Final Notification of Schedule M:** Draft was published in 2018. Final notification made without any changes in the draft. Then, what was his contribution, which was nothing but a big ZERO.
3. **Implementation of QR code:** Notification of QR code on top 300 brands and on API was published much before he joined CDSCO. He had no contribution as he falsely claimed.
4. **Regulatory Rationalization:** It is a continuous process. No any major worth system or regulation made by him in his tenure.
5. **Walk-in-Meeting with Stake holders by the DCGI:** It was not his idea. This was strongly recommended by the then HFM. Hon'ble HFM rather directed him to meet stake holders twice in a week without any appointment as many complaints were found against him were received by the then HFM about his non-availability being the DCGI to the stakeholders.
6. **Kaizen support for productivity improvement:** Again this was not his own idea. It was suggested by the then Health Secretary. He merely executed his instructions, but he claimed it to be his achievement.
7. **Launching of State Drug Regulatory Index:** He made tall claims that he innovated this concept of State Drug Regulatory Index and it was his contribution. But truth is that it is the brain child of the present Health Secretary Madam Ms Punya Srivastava. She directed him to implement this system in the Regulatory System. Ther are so many false claims and achievements made by the Dr.Singh.

8. In nutshell, the real, real, real, real real........fact is that Dr.Raghuvanshi doesn't seem to have any proper idea or knowledge about the Drug Regulations, leave alone expecting him to explain the exact definition of "Drug" as given in the Act. It is an open fact that not even single new policy or procedure or system or regulation or practice was contributed by him during his entire tenure spanning two years. Contrary to his statutory duties, he is well-versed with the vices of corporate style of functioning, the art of misleading the senior Ministry officials in order to earn a certificate of a good officer of indispensable nature, which he has been successful as he managed to send a proposal to the ACC for his re-employment as DCGI on contract with the purpose of allowing him to discharge the statutory duties of the said post of DCGI, which is unheard even in the DoPT. Either he befooled the Ministry officials who had sent the proposal to the DoPT without application of mind. He never allowed any CDSCO officials to interact with Senior Ministry Officials or Minister staff to provide real feed back about him. Unfortunately, they also not asked CDSCO officials in order to verify his false claims. Entire CDSCO officials, State officials, Pharma Industry and even other Govt departments are not at happy with the below average performance and lack of basic regulatory rules/regulations of the Act. But one middle level bureaucrat working in DR Section of the Ministry appearing to be strongly supporting Dr.Raghuvanshi for the reasons best known to him.

I am not requesting the Ministry to enquire or investigate any above facts. Reason is that the Ministry has already fallen in the trap of Dr.Raghuvanshi. Even if the contrary facts are true, no serious view will be taken in the Ministry for the above stated reasons, but efforts are likely to be taken to hush up the matter, trying to silently bury it and defending on his behalf. Because the Ministry seems to have committed on the file that Dr.Raghuvanshi is an asset for CDSCO, having in-depth knowledge, able leadership, bringing substantial reforms etc. But the point is how long the Ministry will play hide and seek from the Truth ? God may alone save the CDSCO.

Satyameva Jayate.

Yours faithfully,

(Khusi Lal Yadav)
8/10, Burari Village
Delhi-110084

Copy for kind information to:

1. Shri J P Nadda, Hon'ble Minister for Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
2. Sh. P.K.Mishra, PS to PM, PMO, South Block, New Delhi-110011
3. Sh. T.V.Somanathan, Cabinet Secretary of India, Rashtrapati Bhawan New Delhi-110004
4. Ms. Rachna Shah, Secretary, DoPT, North Block, New Delhi-110001
5. Ms. Manisha Saxena, Additional Secretary& EO, DoPT, North Block, New Delhi-110001
6. Dr. Atul Goel, DG, DGHS, Ministry of Health & FW, Nirman Bhawan , New Delhi-110011
7. Sri P K Srivastava, Chairman, CVC, Satrakta Bhawan, INA, New Delhi-110023
8. The Director, CBI,New Delhi-110003
9. The Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 7th Floor, D Block, IP Bhawan, New Delhi- 110002
10. The Principal Chief Commissioner of Income Tax, CR Building, IP Estate, New Delhi-110002

MOST SERIOUS COMPLAINT (GRAVEST GRIEVANCE)

DATED: 26.09.2025

To,
Hon'ble Shri Jagat Prakash Nadda Ji
Union Health Minister of India,
Room No. 342, 3rd Floor, Nirman Bhavan, New Delhi-110001

Subject: Complaint about unlawful clearance (smuggling) of the illegal/contraband imported unregulated medical devices (Class C -High Risk Medical Devices) consignments by the Corrupted officers named Sh. Dharamvir Singh, Assistant Drug's Controller (ADC) and Sh. Dinesh Kumar, Drug's Inspector (DI) posted at ADC Office, CDSCO, IGI Air Cargo, New Delhi-reg.

Respected Sir,

Despite having sent the said complaint vide letter no. F.No. Complaint/ACI/CVO/2025/01 dated 08.09.2025 along with several reminders to the **CVO (Ms. Ankita Mishra Bundela (IAS), Joint Secretary, Chief Vigilance Officer)** through email dated 08.09.2025, however no action has been taken yet. Hence therefore, I am compelled to bring to your kind attention a grave matter of corruption and misconduct involving unlawful clearance **(smuggling)** of the illegal/contraband imported unregulated medical devices (Class C -High Risk Medical Devices) consignments by the Corrupted officers of CDSCO i.e. **Sh. Dharamvir Singh, Assistant Drug's Controller (ADC) and Sh. Dinesh Kumar, Drug's Inspector (DI)** posted at ADC Office, CDSCO, IGI Air Cargo, New Delhi-110037.

It has come to my knowledge that on multiple occasions, the above said officers have *released consignments without the mandatory licenses required under Drugs & Cosmetics Act and Medical Devices Rules 2017 there under and sometimes fabricating the documents illegally for releasing the favoured consignments by taking heavy bribery amount.* In this context, respectfully it is to inform you that one such consignment without having the MD-15 (mandatory license for importing medical devices into India) has been imported by the firm named **M/s Tekno Midas Aesthetics**, Rajouri Garden, New Delhi-110027 and same has been released by the above said corrupted officers of CDSCO..

In this regard, please find the details (in tabular format) of unlawful import clearance **(smuggling)** of the illegal/contraband unregulated medical device consignment:-

S.N.	Bill of Entry No. & Date	Name of Product/Medical Device being imported/smuggled	Quantity being imported/smuggled
1.	**3827136** Dated **11.08.2025** (Copy enclosed as **Annexure-A**)	Sterilized absorbable PDO (Polydioxanone) Suture with Needles (Brand Name – DERMA V LINE Lifting Threads)	**2180 Pieces**

MOST SERIOUS COMPLAINT (GRAVEST GRIEVANCE)

Labels of Product/Medical Device	Copy of Labels of Product/Medical Device being imported is enclosed as **Annexure-B** for your ready reference.
Name of Importer and Address	**Tekno Midas Aesthetics,** Vardhman Plaza-1, J-Block Commercial Centre, Shop No. 104, First Floor, Plot No. 3, West Delhi, Rajouri Garden, New Delhi-110027
Country of Origin	Republic of Korea (Copy of Certificate of Origin enclosed as **Annexure-C** for your ready reference)
Name of Supplier/Manufacturer	**Dermaline Co. Ltd.,** D-905,906,914,915, Hanam Techno Valley, U1 Centre, 947, Hanam Daero, Hanam-SI, Gyeonggi-do, 12982, Republic of Korea
Regulated/Classification of Medical Device as per MDR-2017	• Regulated and Classified as **Class C (High Risk Medical Devices)** • Mentioned on Item no. 342 on notice/notification issued by the Drugs Controller General (India) vide File No: 29/Misc./3/2017-DC (292) dated 01.11.2017 regarding the classification of medical devices under the provisions of Medical Devices Rules, 2017 (Copy of same is enclosed as **Annexure-D** for your ready reference)
Whether, firm have mandatory requirement i.e. MD-15 (Import License)	**NO, Importer do not have MD-15.**
Date of NOC issued by ADC on ICEGATE & Out of Charge Date	**Shipment NOC Date** – 28 August 2025 **Shipment Out of Charge Date** – 01 September 2025 **(Copy enclosed as Annexure-E)**
Total Revenue Losses to the Exchequer/Country	3000 USD (Government Fee for One Site Registration) + 1500 USD (Government Fee for One Medical Device Unit) = 4500 USD **(Approx 04 Lakhs INR)**

Note : It has been came to the knowledge that said corrupted officials have taken undertaking for Research Use for the release of above said goods after taking huge amount of bribe – Therefore, it is to clarify that said medical device attracts the definition as per S.O.648(E) dated 11.02.2020 and as per the FAQs (Doc No.: CDSCO/FAQ/MD/01/2024) released by the CDSCO, it is clearly mentioned on point no. 58 that the devices which attracts the definition as per the S.O.648(E) dated 11.02.2020 are regulated under Medical Devices Rules 2017 and a license is required/mandatory under the said rule. Hence therefore, said corrupted officers also have no option to release said goods based on taking undertaking of Research Use from the said importer.

MOST SERIOUS COMPLAINT (GRAVEST GRIEVANCE)

Such actions not only constitute a clear violation of the law/medical devices rules but also **causing substantial revenue losses to the government of India by evading the statutory fees payable for obtaining licenses** and poses a grave threat to the public health and safety and endangering the lives of 1.4 billion citizens of India by allowing or smuggling the unregulated medical devices (Class C -High Risk Medical Devices) into the country. They are not only responsible for result in revenue losses to the exchequer but also undermine the integrity of the healthcare system of India.

Corrupt officers-whether in law enforcement, military, or government institutions-can indeed be considered a **NATIONAL THREAT.**

Hence, therefore, keeping in view of above you are requested to take strict disciplinary action i.e. **Immediate Suspension & High-Level Enquiry (at CBI/CVO, MoH&FW Level) of Sh. Dharamvir Singh, Assistant Drug's Controller (ADC) and Sh. Dinesh Kumar, Drug's Inspector (DI), ADC Office, IGI Air Cargo, New Delhi-110037.**

Thank you for your kind attention. I am very much confident that this afore mentioned matter will receive your immediate consideration in the interest of public at large.

Yours Sincerely,

Pankaj Gupta,
RHB Colony, Near Central Market,
Bhiwadi, Tehsil-Tijara, Dist. Alwar, Rajasthan-301019

अधिकारियों में निराशा और हताशा तेजी से खतरनाक स्तर तक बढ़ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके कनिष्ठ अधिकारी बुरा व्यवहार और अपमान कर रहे हैं, विशेषकर वे कनिष्ठ जो DCGI के नजदीकी हैं। एक व्यक्ति, जिसका नाम श्री दिनेश कुमार है, जो CDSCO, दिल्ली हवाई अड्डे पर औषध निरीक्षक (Drugs Inspector) के रूप में कार्यरत हैं, वह सबसे बड़ा दोषी (culprit) है और DCGI के लिए रिश्वत वसूली (collecting money) कर रहा है, उसके दादा और DCGI आपस में करीबी मित्र हैं। दिनेश कुमार और DCGI, दोनों ही पहले Dr. Reddy's Laboratorie में निजी क्षेत्र में साथ कार्य कर चुके हैं। इसी कारण, अनुभव न होने के बावजूद उसे सबसे मलाईदार पोस्टिंग (cream posting) दी गई है ताकि वह वहाँ से धन एकत्र कर सके। हवाई अड्डे पर वह स्वयं कहता है कि वह "मंत्री JPN के नाम पर वसूली कर रहा है, क्योंकि DCGI को ऊपर तक "JPN और अन्य उच्च अधिकारियों" को देना होता है। इसलिए वह नाम लेकर खुलेआम रिश्वत वसूलता है। यह मामला बहुत गंभीर है और सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। CDSCO में हाल के तबादले (Transfers) मंत्रालय और DOPT की नीति की पूरी तरह अवहेलना में किए गए हैं। अधिकारियों के बीच बढ़ती हुई नाराजगी और असंतोष किसी भी समय विस्फोटक स्थिति में पहुँच सकता है, जिससे सरकार को भारी अपमानजनक स्थिति झेलनी पड़ सकती है। वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है मनमाने, अवैध और भ्रष्ट रघुवंशी तथा कुछ बहुत कनिष्ठ DDCI (Deputy Drug Controller) के कारण, जो मुंबई जोन में हैं। जिन्हें नियामक अनुभव (regulatory experience) तक नहीं है, जिन्होंने न तो कभी निरीक्षण (inspection) किया है, न Show Cause Notice (SCN) जारी किया है, न ही निष्पक्ष सुनवाई (fair hearing) का

(6) 29 JAN 2025

To
Shri J.P Nadda
Hon'ble Union Minister of Health and Family Welfare,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110011.

Sub: Corporate style of resorting to corruption in CDSCO by Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi, DCGI – reg

Respected Sir,

I am a duty-conscious citizen of this country and has been raising public interest issues involving corruption committed by officials at high levels in the Government of India from time to time. Recently I came to know about certain pertaining facts about a so-called honest officer, named as Dr R S Raghuvanshi, who was earlier appointed on short-term contract basis to the high profile post of DCGI, but currently on extension till his retirement on superannuation in February, 2025. I consider it necessary to bring to your kind personal notice about the dark side of the said official which have been concealed by the concerned top officials of the Ministry for the reasons best known to them.

Dr. R S Raghuvanshi, has been making tall claims about his integrity to the Ministry officials, NITI Aayog and PMO beating his own drum that he is honest and joined the CDSCO after leaving high profile job in the private sector. I would like to explain here the motive behind in joining the Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) and subsequently in CDSCO and the modus operandi used for corruption by Dr.Raghuvanshi.

Before he joined IPC, both Dr.Raghuvanshi and his spouse Ms Poonam Raghuvanshi worked in the Dr.Reddys Lab, Hyderabad. Dr.Raghuvanshi got selected for the post of the Director, IPC, Ghaziabad in Feb 2020 and joined IPC in Feb 2021.

Dr.Raghuvanshi with a malafied intention and to resorting to corporate style of corruption in the Government Sector, he started a commercial organisation on August 2020 (after selection for IPC post) in the name of "ipEssentia Intellectual Property Firm" (IIPF) at Noida on his wife name (Poonam Raghuvanshi). This firm is engaged in matters relating to IPR of only Pharmaceutical and Biotech companies. He established this firm before joining in IPC on Feb 2021 with a clear intention that he can influence Pharma and biotech industry representatives as their clients.

The main functions of IIPF are IP litigations, Patent and Trade mark services, IP Strategy and counselling and Product Selection for International registration.

Later on Dr.Raghuvanshi also joined as DCGI in CDSCO on Deputation basis while still holding the post of Director, IPC (holding two critical posts since Feb 2023) with full support from his God Father.

It is commonly understood that generally government servants take bride in Cash form. But in case of Dr.Raghuvanshi, bribe is taken through online transfer to IIPF in the name of consultancy or services provided by the IIPF.

Modus Operand of corruption by Dr.Raghuvanshi:

- He resorted to threatening the pharma/biotech industry forcing them because of his high office and influence to become IIPF clients, which is operated on his wife's name.
- He resorted to demanding pharma company people to transfer money to the IIPF firm in the name of availing the services of that firm.
- Since he holds the critical post of DCGI, having access to all confidential information, he used to pass on all confidential information and data available with the CDSCO office, especially critical drugs, to the IIPF to the firm owned by his wife.
- He also used to share trade secrets relating to manufacturing process of bulk drugs, specifications, flow sheets etc. to the said firm IIPF from CDSCO files.

It is astonishing to notice that Dr.Raghuvanshi has offered space for her wife's firm ie IIPF to setup a stall in the ICDRA exhibition/ conference (Stall number 294) held in New Delhi on October 2024. All pharma companies which are part of exhibition were directed by Dr.Raghuvanshi through his subordinates, to visit IIPF stall and become its clients for services offered by the IIPF.

Office address of IIPF: 1.Noida Address- Meghdutam Apartmnet, Sector 50, Noida. 2. Hyderabad Addrsas - 9th Floor, Block No. D Tower no. III, 902, My Home Bhooja, Hitech City, Hyderabad 500081.

Contact number of Ms. Poonam Raghuvanshi is 8008555339.

Major clinents of IIPF are Glenmark, Abbott, GSK, Novarits, Sentiss pharma, Granules India, Sun pharma, Sanofi, JSS college of Pharmacy, Optimus drugs, Biocon, Dr.Reddys etc.

All above clients have been taking services of IIPF ever since Dr.Raghuvanshi joined IPC and CDSCO. Obviously in blatant misuse of his power and position and also his loyalty to the high officials in the Ministry, and the apparent blessings of his God father he held the license to pressurise the pharma companies to transfer bribe amount to IIPF in the name 'service'. Nobody can dare to challenge his authority of adopting new method of corporate bribe/corruption in IPC and CDSCO. The information given in this complaint are available in the public domain and as such are verifiable and are required to be verified by the Ministry. It is perhaps because of this reason that he intended to cling the post of DCGI by hook or crook even on contract basis in continuation of his extended tenure as DCGI so much so that Ministry officials were apparently on their knees to send a proposal in this regard seeking DoPT approval for his re-employment on contract basis vide letter dated 17/01/2025, even contrary to the extant rules. All these facts may be verified from the Ministry.

As per the Conduct Rules, no family member of a Government Servant can be engaged in the business which is having conflict of interest with the officer. The statutory Act of the Drugs and Cosmetics Act also prohibits appointment of any officer (DCGI) doing any business which has any financial interest in the pharma. In this case, DCGI is directly engaged in doing pharma business (IP matters/litigations) on his wife's name. It is surprising if Dr. Raghuvanshi has concealed this information to the Ministry as he is duty bound to voluntarily furnish such information or if he had furnished such information in a cryptic manner and the concerned officials in the Ministry overlooked this, for the reasons best known to them, it is a matter of serious nature needling a thorough inquiry.

It is requested to carryout detailed investigation on above matter immediately by the independent committee on fallowing areas:

1. How many pharma/Biotech companies are engaging services of IIPF, owned by Dr.Raghuvanshi's wife.
2. How many Multi National pharma companies have taken services of IIPF as a consultant service provider.
3. Income Tax retunes submitted by the IIPF for the periods 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024. Please verify the growth of the business. You will be surprised to see that 300 to 800% growth in revenues during this period.
4. Data and information of various Multi National Pharma companies shared by the Dr.Raghuvanshi to IIPF.
5. How could IIPF set up stall in the ICDRA exhibition, when it is owned by the DCGI's wife. How many pharma companies visited this stall as IIPF has maintained visitor's dairy at the Stall.

Note: Dr.Raghuvanshi informed to all pharma industry people that he is very close to Sh. P.K.Mishra, Principal Secretary to the PM. Hence no one can dare to question his wife's business.

Satyameva Jayate.

Yours faithfully,

(Khusi Lal Yadav)
8/10, Burari Village
Delhi-110084
CC. For information and necessary action to:

1. Sh. P.K.Mishra, PS to PM, PMO, Soth Block, New Delhi-110011
2. Sh. T.V.Somanathan, Cabinet Secretary of India, Rashtrapati Bhawan New Delhi-110004
3. Sh. B.V.R.Subrahmanyam, CEO, NITI Aayog, New Delhi-110001
4. Ms. Rachna Shah, Secretary, DoPT, North Block, New Delhi-110001
5. Sh. Arunish Chawala , Secretary, Pharmaceuticals, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
6. Ms. Punya Salila Srivastava, Secretary, Department of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
7. Ms. Manisha Saxena, Additional Secretary & EO, DoPT, North Block, New Delhi-110001
8. Dr. Rajiv Bahl, DG, ICMR, Deptt of Health & Research, Ansari Nagar New Delhi-110029
9. Dr. Atul Goel, DG, DGHS, Ministry of Health & FW, Nirman Bhawan , New Delhi-110011
10. Sri P K Srivastava, Chairman, CVC, Satrakta Bhawan, INA, New Delhi-110023
11. The Director, CBI New Delhi-110003
12. The Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 7th Floor, D Block, IP Bhawan, New Delhi- 110002
13. The Principal Chief Commissioner of Income Tax, CR Building, IP Estate, New Delhi-110002

अनुभव है। फिर भी वे "उच्च अधिकारियों के आदेश" के नाम पर राज्य स्तर पर अधिकारियों पर दबाव डालते हैं कि वे तुच्छ मामलों में तुरंत कार्रवाई करें। यदि आप देखें - पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर CDSCO जोनल या सब-जोनल कार्यालय में कनिष्ठ या गैर-प्रवर्तन (non-enforcement) पृष्ठभूमि वाले तकनीकी अधिकारी प्रमुख पदों पर बैठे हैं, जबकि वे वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने भ्रष्ट आदेशों को मानने से इनकार किया, उन्हें किनारे कर दिया गया है। उदाहरणस्वरूप श्रीनिवास, DDC (दक्षिण जोन), संतोष इंद्राक्ष, DDC (पश्चिम जोन) दोनों ही कनिष्ठतम अधिकारी हैं और उन्होंने कभी कोई निरीक्षण नहीं किया है। अजय सचन, DDC (उत्तर जोन), वरिष्ठता में बहुत नीचे हैं और हाल ही में DDC बने हैं। अरूप चटर्जी, DDC (पूर्वी जोन), तकनीकी अधिकारी पृष्ठभूमि से हैं, जो तलाशी, जब्ती, अभियोजन या लाइसेंसिंग प्राधिकरण का कार्य; यहाँ तक कि "Dual Use NOC" या "Test License" जैसे मामलों में भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार रविकांत शर्मा, DDC (अहमदाबाद जोन), तकनीकी पृष्ठभूमि से हैं और उनके पास भी नियामक अधिकार (regulatory powers) नहीं हैं। अब बंदरगाह कार्यालयों (Port Offices) पर भी DDC की पोस्टिंग की जा रही है, जहाँ न तो कोई पद स्वीकृत है और न आवश्यकता। यह सब सौदेबाजी और लाभ के आदान-प्रदान के लिए किया जा रहा है। उदाहरण :-पी. मणिवालन, DDC, चेन्नई समुद्री बंदरगाह, पी. इंदिरा, DDC, हैदराबाद (शम्शाबाद एयरपोर्ट) जहाँ वास्तव में कोई DDC पद नहीं है, लेकिन उन्हें किसी और को समायोजित करने के लिए वहाँ भेजा गया है। यदि आप DDC वरिष्ठता सूची (Seniority List) देखें, तो पाएँगे कि अत्यधिक अनुभवी अधिकारी जैसे:- B.K. Samantray, HQ, A. Senkathir, HQ (कानूनी विभाग) इनको जानबूझकर किनारे कर दिया गया है। बी. कुमार, DDC को अचानक गुवाहाटी भेज दिया गया। प्रतिशोध स्वरूप (as punishment transfer)। इसी प्रकार के. नरेंद्रन, जो कनिष्ठ अधिकारी थे, पहले चेन्नई सीपोर्ट के DDC थे, अब हैदराबाद DDC बना दिए गए हैं। सुनील कुलश्रेष्ठ, असीम साहू और श्री हूरा इन सब को दिल्ली से कभी ट्रांसफर नहीं किया गया। स्वाति श्रीवास्तव, DDC को पिछले 20 वर्षों में कभी दिल्ली (या अधिकतम गाजियाबाद) से नहीं हटाया गया। अनेक उदाहरण इस बात के हैं कि DGHS (Director General of Health Services) क्या कर रहे है, जो कि "मंजूरी देने वाली प्राधिकृत अधिकारी (approving authority)" हैं। संभवत: उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनकी मंजूरी के तहत एक बड़ा घोटाला (BIG SCAM) चलाया जा रहा है। अपनी पसंदीदा पोस्टों पर अधिकारियों को रखकर धन उगाही करने के अलावा DCGI ने अपनी पत्नी की Intellectual Property Rights (IPR) Consulting Firm के नाम पर सीधी रिश्वतखोरी के माध्यम से करोड़ों रुपये कमाए हैं। उन्होंने फार्मा सेक्टर के चुनिंदा मित्रों को कई लाभ पहुँचाए और बदले में उनकी पत्नी की फर्म के माध्यम से कमीशन और किकबैक प्राप्त किए। उनकी पत्नी की फर्म केवल एक आवरण (sham entity) है, जो डॉ. राजीव रघुवंशी की अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए बनाई गई है। उनके प्रभाव में कई अवैध भर्तियाँ IPC में की गई और इसलिए मंत्रालय ने भी नई नियुक्ति प्रक्रिया रोक रखी है, ताकि उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों को कानूनी जांच से बचाया जा सके। सरकारी अधिकारी, जो IPC की फाइलों से संबंधित कार्य देखते हैं, वे सब डॉ. राजीव रघुवंशी के साथ मिलीभगत में हैं। इन अधिकारियों और नियुक्त व्यक्तियों के नाम सरल जाँच से सामने लाए जा सकते हैं। उनके द्वारा किया गया शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार अब चौंकाने वाले स्तर (astonishing level) पर पहुँच चुका है। मंत्रालय की लंबे समय से निष्क्रियता विभिन्न हितधारकों (व्यक्तिगत या समूहों) द्वारा दर्ज कराई गई। कई शिकायतों के बावजूद यह दर्शाती है कि कुछ अधिकारी स्वयं भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पहले भी उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग, IPC में अपने लोगों की नियुक्ति और मंत्रालय व DOPT के भर्ती नियमों की अवहेलना से संबंधित कई शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने SSO (Senior Scientific Officer) की अल्पावधि अनुबंध नियुक्ति सभी सरकारी नियमों (DOPT और IPC भर्ती उपनियमों) की अनदेखी करते हुए की, जिससे योग्य और पात्र उम्मीदवारों की पूर्ण अनदेखी हुई। यदि इन पर गहन जाँच (thorough enquiry) की जाए, तो यह स्पष्ट रूप से एक बड़ा भर्ती घोटाला (major recruitment scam) सिद्ध होगा।

पूनम रघुवंशी

डॉ. राजीव रघुवंशी का मंत्रालय में सहायक और सहयोगी श्री किरण कुमार कारलापू, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय में निदेशक हैं, उनके निर्देश पर डॉ. रघुवंशी ने कई ऐसी कंपनियों की फाइलें अनुचित रूप से

कफ सीरप से बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया हैरान करने वाला

- शुक्रवार को दे दी थी कफ सीरप को क्लीन चिट, बाद एडवाइजरी जारी कर निश्चित हो गया
- तमिलनाडु की जांच में डीईजी मिलने के बाद भी खानापूर्ति में जुटा रहा मंत्रालय

THE HINDU

Tamil Nadu

Central officials did not carry out drug inspections in T.N. for 6 years: Health Minister

Responding to allegations against the T.N. govt. in the cough syrup case, he says two senior drug inspectors from the State have been placed under suspension for failing to conduct yearly checks

राजस्थान : सिरप में नहीं मिले घातक साल्वेंट

केयसंस फार्मा की सिरप को जांच में क्लीन चिट, सभी सैंपल पास

जयपुर के सरना डूंगर की है यह दवा निर्माता कंपनी

पत्रिका ने पहले बताया

राजाराम निलंबित, धीर को चार्ज

पास कीं, जो दोनों के करीबी संबंधों में थीं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इस पद पर नई भर्ती न हो, जिसके परिणामस्वरूप IPC के अनेक सक्षम अधिकारियों के करियर बर्बाद हो गए। यह सब कुछ उन्होंने मंत्रालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से किया, जो IPC की गाड़ियों और संसाधनों का दुरुपयोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए करते हैं। उनके प्रभाव में कई अवैध भर्तियाँ IPC में की गई और इसलिए मंत्रालय ने भी नई नियुक्ति प्रक्रिया रोक रखी है, ताकि उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों को कानूनी जांच से बचाया जा सके। सरकारी अधिकारी, जो IPC की फाइलों से संबंधित कार्य देखते हैं, वे सब डॉ. राजीव रघुवंशी के साथ मिलीभगत में हैं। उन्होंने बाहरी व्यक्तियों को IPC में नियुक्त कर वहाँ कार्यरत कर्मचारियों का उत्साह और मनोबल तोड़ दिया है। मंत्रालय की लंबे समय से निष्क्रियता विभिन्न हितधारकों (व्यक्तिगत या समूहों) द्वारा दर्ज कराई गई। कई शिकायतों के बावजूद यह दर्शाती है कि कुछ अधिकारी स्वयं भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पहले भी उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग, IPC में अपने लोगों की नियुक्ति और मंत्रालय व DOPT के भर्ती नियमों की अवहेलना से संबंधित कई शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। उनके कार्यकाल में हुई सभी नियुक्तियाँ किसी भी प्रकार से सरकारी मानकों, पात्रता या नियमों पर खरी नहीं उतरतीं। यदि इन पर गहन जाँच (thorough enquiry) की जाए, तो यह स्पष्ट रूप से एक बड़ा भर्ती घोटाला (major recruitment scam) सिद्ध होगा। डॉ. राजीव रघुवंशी का मंत्रालय में सहायक और सहयोगी श्री किरण कुमार कारलापू, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनके निर्देश पर डॉ. रघुवंशी ने कई ऐसी कंपनियों की फाइलें अनुचित रूप से पास कीं, जो दोनों के करीबी संबंधों में थीं। उन्होंने DCGI से करोड़ों रुपये की रिश्वत लेकर उन फाइलों को मंजूरी दी। DCGI (Drugs Controller General of India) भारत के औषधि नियंत्रक महानियंत्रक हैं, जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के प्रमुख होते हैं। वर्तमान DCGI डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी हैं, जिन्होंने फरवरी 2023 में पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 तक था, जिसे हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके अनुभव के आधार पर बढ़ाने का अनुरोध किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग में CDSCO और DCGI से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं। ये आरोप रिश्वतखोरी, नकली दवाओं की मंजूरी, MSME इकाइयों पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई और नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े हैं। हालांकि, ये ज्यादातर सामान्य उद्योग-स्तरीय हैं और डॉ. रघुवंशी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष, सिद्ध कानूनी कार्रवाई या आधिकारिक जांच की पुष्टि नहीं हुई है।

☞ **फार्मा उद्योग में भ्रष्टाचार के सामान्य आरोप नकली और घटिया दवाओं का मामला :-** अक्टूबर 2024 में, DCGI ने 45 दवा निर्माताओं को गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने वाली दवाओं को वापस बुलाने का आदेश दिया। साथ ही 5 नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई। DCGI राजीव सिंह रघुवंशी ने स्पष्ट किया कि CDSCO हर महीने 2,000 से अधिक नमूने जांचता है, जिनमें से 40-50 विफल होते हैं, लेकिन ये "नकली" नहीं बल्कि गुणवत्ता-समस्या वाले होते हैं। एक रिपोर्ट में 50 दवाओं पर "प्रतिबंध" की अफवाह फैली, जिसे DCGI ने गलत बताया।

☞ **फार्मा सेक्टर में 'रोट' (भ्रष्टाचार) :-** एक विश्लेषण में कहा गया कि CDSCO और DCGI के अधिकारियों पर नकली दवाओं की मंजूरी और छोटे उद्योगों को बंद कराने के आरोप लगते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय QR कोड सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है ताकि दवाओं की ट्रेसिबिलिटी बढ़े। जनवरी 2025 में सरकार ने DCGI के पद के लिए 18 उम्मीदवारों की जांच की, लेकिन वर्तमान DCGI को अनुभव के कारण बनाए रखा। दिनांक-21/10/2025 को राजीव रघुवंशी के सहयोगी निदेशक किरण कुमार कारलापु ने DCGI पद के लिए निकले गए Advertisement No& A-12025/01/2024 को केन्सिल कर दिया, ताकि श्री राजीव रघुवंशी की बादशाहत बनी रहें।

☞ **मिसलीडिंग जानकारी पर कार्रवाई अक्टूबर 2024 में :-** DCGI ने दवा कंपनियों को चेतावनी दी कि गलत या भ्रामक जानकारी देने पर उन्हें डिबार (प्रतिबंधित) किया जाएगा। DCGI से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप फार्मा उद्योग की पुरानी समस्या हैं, जो रिश्वत, नियुक्तियों और नियामक ढील से जुड़े विश्लेषकों का मानना है कि भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य नियामक निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या भेदभाव की गुंजाइश न रहे। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच ही उद्योग में विश्वास बहाल कर सकती है।

(आप पढ़ते रहिए केवल सच। अगले अंक में हम श्री राजीव रघुवंशी और पूनम रघुवंशी के अवैध कमाई के साथ-साथ अवैध रिश्तों का भी खुलासा करेंगे।)

शिक्षा, पलायन और रोजगार
आखिरी पारी, आखिरी दाव

● अमित कुमार

बिहार विधानसभा की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी की पर्व और त्यौहारों को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को दो चरणों में कराया जायेगा, जिसकी तिथि 6 नवम्बर (121 सीटों पर) और 11 नवम्बर (122 सीटों पर) सुनिश्चित हुई है तथा इसके परिणाम 14 नवम्बर को घोषित किये जायेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सक्रिय हो गये। एनडीए और महागठबंधन दोनो दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में काफी देरी दिखायी। हालांकि एनडीए ने अपने घटक दलों के बीच सीट बंटवारों में एकजुटता दिखाते हुए महागठबंधन से पहले अपने उम्मीदावारों की लिस्ट जारी कर दी। जिनमें भाजपा 101, जदयू 101, लोजपा (आर) 28, हम 6 और रालोमो 6 सीटों के साथ चुनावी मैदान में हैं। वही दूसरी तरफ महागठबंधन में सामंजस नहीं बन पाने के कारण कई दल के नेता ने बिना आपसी समझौते के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सिम्बल भी बांटना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिये हैं। हालांकि सीटों के आंकड़े को लेकर कांग्रेस-राजद की नाराजगी के साथ ही वीआईपी की भी नाराजगी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में देरी की। अंततः सीटों का अंतिम सहमती बन गई। इसके बाद राजद 143, कांग्रेस 61, सीपीआई (एम एल) 20, वीआईपी 12, सीपीआई 9, सीपीआई (एम) 4 सीटों के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही महागठबंधन ने इस चुनाव में आईआईपी को भी 3 सीटे दी है। एनडीए और महागठबंधन ने अपने-अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और दो चरणों के चुनाव को लेकर नामांकन भी हो चुका है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया में त्रुटी के कारण कुछ उम्मीदवारों का नामांकन भी रद्द हो चुका है। बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन के अलावे जीडीए (ग्रांड डेमोक्रेटिव एलायंस) भी है, जिनमें एआईएमआईएम 25 सीटों पर, रालोजपा 25, आसपा (का०) 25 और आजपा 4 सीटों पर मैदान में है। साथ ही बसपा 130, आप 121, जन सुराज 116 और जनशक्ति जनता दल 22 सीटों के साथ चुनावी मैदान में है।

गौरतलब है कि चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी जोरो पर है और राज्य में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए चार लाख से अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गये हैं। इसमें करीब 1500 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती की गयी है। इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल, रिजर्व बटालियन, होमगार्ड, चौकदीर आदि की ड्यूटी लगाई जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने

बताया कि पहली बार चुनाव के दौरान दूरदराज के इलाकों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षाकर्मियों को हेलीकाप्टर से नहीं उतारा जाएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण इस बार सभी बल सड़क मार्ग से ही अपने तैनाती स्थलों तक पहुंचेंगे। राज्य में नक्सली गतिविधियों में कमी के कारण इस बार किसी भी मतदान केंद्र को स्थानांतरित भी नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि चुनाव से पहले ही सीएपीएफ की लगभग 500 कंपनियां विभिन्न जिलों में तैनात की जा चुकी हैं और 500 कंपनियां बहुत जल्द बिहार पहुंच जाएंगी, जिन्हें मतदान केंद्रों के आसपास तैनात किया जाएगा। एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। इस तरह 1500 कंपनी केंद्रीय बलों में करीब डेढ़ लाख सुरक्षा बल शामिल होंगे। केंद्रीय बलों के अलावा बिहार पुलिस के 60 हजार कर्मियों को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके साथ दूसरे राज्यों से आये रिजर्व बटालियनों के दो हजार जवान, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 30 हजार जवान, 20 हजार से ज्यादा होमगार्ड और लगभग 19 हजार प्रशिक्षु सिपाहियों को भी चुनावी कार्य में लगाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में लगभग 1.5 लाख चौकीदार भी चुनाव में ड्यूटी करेंगे। बता दें कि बिहार में पिछले 25 वर्षों (2000 से अब तक) में पहली बार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में हो रहा है। इससे पहले बिहार में कभी भी दो चरणों में चुनाव नहीं हुए हैं। इससे पहले के चुनावों में चरणों की संख्या तीन से अधिक रही, जो सुरक्षा, भूगोल और अन्य कारणों से तय होती थी। 2000 के चुनाव में झारखंड के गठन के बाद बिहार की सीटें 324 से घटकर 243 हो गई थीं। उसके बाद चरणों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन 2025 में आयोग ने दलों की सहमति से इसे घटाकर दो कर दिया है।

बहरहाल, वर्षों से पार्टी का झंडा ढ़ोते आ रहे कार्यकर्ता पार्टी सिम्बल की उम्मीद में कसरत करते दिखे। दलों से टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों को कड़े पापड़ बेलने पड़े। जिसे पार्टी का सिम्बल

मिला उसकी बल्ले-बल्ले और जिन्हे नहीं मिला उनके अजीबों गरीब कारनामे सुर्खिया में बने। ऐसे कई नेता अपनी हरकतों से मीडिया का टीआरपी बढ़ाने का काम किया किन्तु गोपाल मंडल और मदन साह सबसे टॉप पर रहे। वही राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। मधुबन से टिकट के दावेदार मदन साह ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास दस सर्कुलर के बाहर हंगामा किया। कुर्ता फाड़ लिया और दहाड़ मारकर रोने लगे। राजद के कई नेता पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा देने लगे हैं। मधुबन से पिछला चुनाव लड़ चुके मदन साह टिकट नहीं मिलने पर राबड़ी आवास के बाहर फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने दावा किया कि उनसे टिकट के लिए करोड़ों रुपए मांगे गए और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उनका टिकट काट दिया गया। वे इतने आक्रोश में थे कि उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ लिया। कहा कि मैं 1990 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं लेकिन अब टिकट पैसों के बल पर बांटे जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता दिन-रात पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, उन्हें किनारे कर दिया गया है। बाराचट्टी की दावेदार उषा देवी भी राबड़ी आवास के बाहर रोती हुई दिखाई दीं। कहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर किसी अन्य उम्मीदवार को चुना, जिससे वे बेहद आहत हो गई। उषा ने कहा कि मेरे पास पैराशूट नहीं था। उषा देवी ने कहा कि मैं 17 साल की उम्र से पार्टी की सदस्य हूं। मैं निराश हूं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव और लालू यादव का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। राजद के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करूंगी। बिहारशरीफ के पप्पू खान इस सीट के कांग्रेस में जाने और बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाया और कहा कि वे राजद को अब देखना भी नहीं चाहेंगे। पप्पू खान ने पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का एलान किया। बरौली से पिछला चुनाव लड़ चुके रियाजुलहक उर्फ राजू इस बार टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान कर चुके हैं। सासाराम की दावेदार अर्चना गुप्ता ने भी बगावत कर दी है। अर्चना ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कानू समाज से हर हाल में एक नेता को टिकट देने का आश्वासन दिया था लेकिन वे अपनी बात पर टिक नहीं सके। बाढ़ की जिलाध्यक्ष नम्रता नीरज सिंह ने भी बगावती तेवर अपनाते हुए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। बांका के जिला प्रधान महासचिव और बेलहर के दावेदार मिठन यादव ने पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दल से त्यागपत्र दे दिया। वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि जिस दल का जनाधार बड़ा है, कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी है और जीतने की संभावना भी ज्यादा है तो उस दल में टिकट के दावेदारों की संख्या भी ज्यादा होना स्वाभाविक है। टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। गठबंधन की राजनीति में तो क्षेत्रों

फोन नं०- 0612-2506830
ई-मेल-rjdbihar2019@gmail.com

राष्ट्रीय जनता दल,बिहार

2,वीरचंद पटेल पथ,पटना-800001

प्रत्रांक..... दिनांक.....

कार्यालय आदेश

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत उम्मीदवारों के विरूद्ध निम्नलिखित पार्टी के साथियों के द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध दल विरोधी आचरण, क्रियाकलाप एवं प्रतिकूल सक्रिय गतिविधियाँ करने के बारे में पार्टी के राज्य मुख्यालय को प्राप्त अधिकृत सूचना के आधार पर पार्टी के निम्नलिखित नेताओं/कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम	जिला/क्षेत्र
1	श्री फतेह बहादुर सिंह, विधायक	डेहरी
2	श्री सतीश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजद, बिहार	नालंदा
3	मो0 सैययद नौसादुल नवी उर्फ पप्पू खां	बिहार शरीफ
4	मो0 गुलाम जिलानी वारसी, पूर्व विधायक	कांटी
5	मो0 रियाजुल हक राजू, पूर्व विधायक	गोपालगंज
6	श्री अमोद कुमार मंडल, प्रदेश महासचिव, राजद, बिहार	पूर्णियां
7	श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, क्रियाशील सदस्य	सिंहेश्वर
8	ई0 प्रणव प्रकाश, क्रियाशील सदस्य	मधेपुरा
9	श्रीमती जिप्सा आनंद, प्रदेश महासचिव, महिला प्रकोष्ठ सह जिला परिषद सदस्य	भोजपुर
10	श्री राजीव रंजन उर्फ पिंकू, राजद नेता, क्रियाशील सदस्य	भोजपुर

24.10.25

(मंगनी लाल मंडल)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय जनता दल, बिहार।

बिहार प्रदेश जनता दल (यूनाईटेड)

1, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001
दूरभाष नं0-0612-2228055, 2506607, 2506256
E.Mail-jdubihar@gmail.com, jdubihar@yahoo.in

पत्रांक : 585/25 दिनांक : 25/10/25

निदेशानुसार, बिहार विधान सभा आम चुनाव 2025 में पार्टी की विचारधारा, पार्टी विरोधी गतिविधियों एवं संगठनात्मक आचरण के विरूद्ध कार्य करने में संलिप्त रहने के कारण आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए पार्टी से निष्कासित किया जाता है।

भवदीय

(चन्दन कुमार सिंह)
प्रदेश महासचिव एवं
(मुख्यालय प्रभारी, स्थापना)

सेवा में,
श्री शैलेश कुमार, पूर्व मंत्री, जमालपुर, मुंगेर।
श्री संजय प्रसाद, पूर्व स0वि0प0, चकाई, जमुई।
श्री श्याम बहादुर सिंह, पूर्व स0वि0स0, बडहरिया, सीवान।
श्री रणविजय सिंह, पूर्व स0वि0प0, बड़हरा, भोजपुर।
श्री सुदर्शन कुमार, पूर्व स0वि0स0, बरबीधा, शेखपुरा।
श्री अमर कुमार सिंह, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय।
डॉ आसमा परवीन, महुआ, वैशाली।
श्री लब कुमार, नवीनगर, औरंगाबाद।
श्रीमती आशा सुमन, कदवा, कटिहार।
श्री दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।
श्री विवेक शुक्ला, जिरादेई, सीवान।

की संख्या भी सीमित होती है। ऐसी स्थिति में जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता है वे भावावेश में आकर यदि कुछ टिप्पणियां करता है तो उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता।

सनद् रहे कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 10 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें एक ऐसे विधायक भी शामिल हैं, जो टिकट न मिलने पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। राजद के वर्तमान डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह, पार्टी के डेहरी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय मैदान में हैं। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एक बयान में कहा कि निष्कासित नेताओं में एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बयान के मुताबिक डेहरी से राजद के वर्तमान विधायक फतेह बहादुर सिंह, पूर्व विधायक मो. गुलाम जिलानी वारसी (कांटी) और मो. रियाजुल हक राजू (गोपालगंज) को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार (नालंदा), बिहार शरीफ से मो. सैयद नौसादुल नवी उर्फ पप्पू खां, पूर्णिया के प्रदेश महासचिव अमोद कुमार मंडल, सिंहेश्वर के क्रियाशील सदस्य विरेंद्र कुमार शर्मा, मधेपुरा से ई. प्रणव प्रकाश, भोजपुर से महिला प्रकोष्ठ की महासचिव जिप्सा आनंद और भोजपुर के ही सक्रिय सदस्य राजीव रंजन उर्फ पिंकू पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की गई। इसके पूर्व 27 नेताओं को दल से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद शामिल हैं। प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि निष्कासित नेता या तो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में है या वे महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। सभी को 6 साल के लिए निष्काषित किया गया है। बता दें कि आरजेडी से निष्कासित 27 नेताओं में छोटे लाल यादव, विधायक-परसा, रितु जायसवाल-परिहार, राम प्रकाश महतो, पूर्व विधायक-कटिहार, अनिल सहनी, पूर्व विधायक-मुजफ्फरपुर, सरोज यादव, पूर्व विधायक-बड़हरा, गणेश भारती, पूर्व विधान पार्षद- मुजफ्फरपुर, मो. कामरान, विधायक- गोविंदपुर, अनिल यादव, पूर्व विधायक- नरपतगंज, अक्षय लाल यादव, पूर्व प्रत्याशी-चिरैया, राम सखा महतो, जिला प्रधान महासचिव-चेरिया, बरियापुर, अवनीष कुमार, राज्य परिषद सदस्य- भागलपुर, भगत यादव- शेरघाटी, मुकेश यादव-संदेश, संजय राय, जिला प्रधान, महासचिव- वैशाली, कुमार गौरव, उपाध्यक्ष अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ-दरभंगा, राजीव कुशवाहा, जिला महासचिव-दरभंगा, महेश प्रसाद गुप्ता, जिलाध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ-जाले, वकील प्रसाद यादव-जाले, पूनम देवी गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष-मोतिहारी, सुबोध यादव, पूर्व अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ-मोतिहारी, सुरेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव सेनपुर-सारण, नीरज राय-वैशाली, अनिल चंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव- भागलपुर, अजीत यादव, जिला प्रवक्ता सुल्तानगंज- भागलपुर, मोती यादव, गोपालपुर- पूर्वी चंपारण, रामनरेश पासवान, चिरैया प्रखंड अध्यक्ष-पूर्वी चंपारण, अशोक चौहान, पताही प्रखंड अध्यक्ष शामिल हैं। दिगर बात है कि पार्टी विरोधी कार्य को लेकर कार्रवाई करने में जदयू भी पीछे नहीं है। जदयू ने भी बागियों पर एक्शन लिया है। जदयू ने अपने विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल सहित पांच लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गोपाल मंडल के अलावा जिन अन्य चार लोगों को जदयू ने दल से निकाला है उनमें पूर्व मंत्री हिमराज सिंह, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव व गायघाट के प्रभात किरण शामिल हैं। इनके निष्कासन आदेश में कहा गया है कि ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। मालूम हो कि जदयू ने पूर्व मंत्री शैलेश कुमार सहित 11 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इनमें पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह, विधायक सुदर्शन कुमार, साहेबपुर कमाल के अमर कुमार सिंह, जदयू के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़ी आस्मां परवीन, नवीनगर के लव कुमार, मोतिहारी के दिव्यांशु भारद्वाज, कदवा से आशा सुमन व जीरादेई के विवेक शुक्ला शामिल हैं। गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में कई बागी हैं जो दलीय उम्मीदवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पार्टी

से टिकट नहीं मिलने के बाद ये जनता की अदालत में पहुंच गए हैं। इनमें सभी दलों का हाल एक जैसा ही है। विधायक गोपाल मंडल, इरफान आलम, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जैसे प्रमुख नेता बागी बनकर मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे बागियों की वजह से दलीय उम्मीदवारों को वोट बंटने और हार का डर सता रहा। बात करें गोपाल मंडल की तो वे भागलपुर जिले के गोपालपुर सीट से लगातार तीन बार जदयू के टिकट पर निर्वाचित होते रहे। इस बार पार्टी ने उनकी जगह शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को टिकट दे दिया। इससे गोपाल मंडल नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह ने भी बागी तेवर अपना लिया है। रोहतास की दिनारा सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाने पर उन्होंने निर्दलीय ही ताल ठोंक दी है। उधर शेखपुरा जिले के बरबीघा से सुदर्शन कुमार की जगह जदयू ने कुमार पुष्पंजय को उम्मीदवार बना दिया तो सुदर्शन कुमार भी मैदान में उतर गए।

बताते चले कि किसी भी प्रमुख चुनाव से पहले नई-नई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का जन्म लेना और पार्टियों में अचानक नेताओं की बाढ़ आना सामान्य बात है। जहां प्रमुख पार्टियों में संभावनाएं तलाश रहे नेताओं ने अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इसके लिए इन लोगों ने सीधे तौर पर पार्टी मंचों से अधिक, अपनी पहचान जनता के बीच स्थापित करने के लिए 'पोस्टर पॉलिटिक्स' का सहारा लिया, लेकिन अब टिकट वितरण के बाद इन महत्वाकांक्षी नेताओं की निराशा इंटरनेट मीडिया पर 'लोकल फॉर वोकल' का शोर मचा रही है। चुनावी टिकट की असली जंग ने कई नेताओं को उनकी वास्तविक स्थिति का एहसास करा दिया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रमुख पार्टियों से जुड़ने वाले नेता अपनी जीत की संभावना अधिक देखते हैं। खुद को जनता का हमदर्द और स्थानीय शुभचिंतक बताने की होड़ में इन नेताओं ने शहर में पोस्टर युद्ध छेड़ दिया। शहर के चौक-चौराहों से लेकर गली-मोहल्लों तक, पर्व-त्योहारों की शुभकामनाओं वाले पोस्टरों की भरमार हो गई। सड़कों पर लगे बिजली के खंभे इनके पोस्टर से पट गए। दीपावली हो या छठ पूजा, हर अवसर पर इन नेताओं ने बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर यह दर्शाने की कोशिश की कि जनता से बड़ा उनका कोई हितैषी नहीं है। कुछ नेता तो चुनावी गहमागहमी को देखते हुए अंतिम समय में इस 'पोस्टर युद्ध' में कूदे। कुल मिलाकर, माहौल बनाने के लिए पोस्टर पर खूब पैसा और प्रयास खर्च किया गया। शहर में हुए पार्टी के कार्यक्रमों में भी इन लोगों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया या यूं कहें कि जिसको जिस विधानसभा से टिकट मिलने की उम्मीद थी, उन्होंने उस विधानसभा में खास ध्यान दिया। ये लगातार अपने चहेते नेताओं के संपर्क में रहे, ताकि पार्टी आलाकमान की नजर इन पर पड़े और टिकट की दावेदारी पुख्ता हो सके, लेकिन आखिर तक इनकी यह पोस्टर पालिटिक्स काम नहीं आ सकी। पोस्टर के सहारे माहौल बनाने वाले ये नेता पार्टी को अपनी दावेदारी के लिए राजी नहीं कर पाए। टिकट वितरण के अंतिम चरण में इन सभी महत्वाकांक्षी चेहरों को पार्टी ने किनारे कर दिया। सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई और इन्हें निराशा हाथ लगी। पार्टी द्वारा टिकट से किनारा किए जाने के बाद, ये निराश टिकटार्थी अब एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं। ये सभी अब इंटरनेट मीडिया पर 'लोकल फॉर वोकल' का राग अलाप रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण

Constituency	NDA		MGB	
Valmiki Nagar	JD(U)	Dhirendra Pratap Singh	INC	Surendra Prasad Kushwaha
Ramnagar (SC)	BJP	Nand Kishore Ram	RJD	Subodh Paswan
Narkatiaganj	BJP	Sanjay Pandey	INC	Shaswat Kedar Pandey
			RJD	Deepak Yadav
Bagaha	BJP	Ram Singh	INC	Jayesh Mangal Singh
Lauriya	BJP	Vinay Bihari	VIP	Ran Kaushal Pratap Singh
Nautan	BJP	Narayan Prasad	INC	Amit Giri
Chanpatia	BJP	Umakant Singh	INC	Abhishek Ranjan
Bettiah	BJP	Renu Devi	INC	Wasi Ahmed
Sikta	JD(U)	Sammridh Varma	CPI(ML)L	Birendra Prasad Gupta
Raxaul	BJP	Pramod Kumar Sinha	INC	Shyam Bihari Prasad
Sugauli	LJP(RV)	Rajesh Kumar	None	
Narkatiya	JD(U)	Vishal Shah	RJD	Shamim Ahmad
Harsidhi (SC)	BJP	Krishnanandan Paswan	RJD	Rajendra Kumar Ram
Govindganj	LJP(RV)	Raju Tiwari	INC	Shashi Bhushan Rai
Kesaria	JD(U)	Shalini Mishra	VIP	Varun Vijay
Kalyanpur	BJP	Sachindra Prasad Singh	RJD	Manoj Kumar Yadav
Pipra	BJP	Shyambabu Prasad Yadav	CPI(M)	Raj Mangal Prasad
Madhuban	BJP	Rana Randhir Singh	RJD	Sandhya Rani Kushwaha
Motihari	BJP	Pramod Kumar	RJD	Dewa Gupta
Chiraia	BJP	Lal Babu Prasad Gupta	RJD	Lakshmi Narayan Prasad Yadav
Dhaka	BJP	Pawan Jaiswal	RJD	Faisal Rahman
Sheohar	JD(U)	Shweta Gupta	RJD	Navneet Kumar
Riga	BJP	Baidyanath Prasad	INC	Amit Kumar Tunna
Bathnaha (SC)	BJP	Anil Kumar Ram	INC	Navin Kumar
Parihar	BJP	Gayatri Devi	RJD	Smita Purve Gupta
Sursand	JD(U)	Nagendra Raut	RJD	Syed Abu Dojana
Bajpatti	RLM	Rameshwar Mahto	RJD	Mukesh Yadav
Sitamarhi	BJP	Sunil Kumar Pintu	RJD	Sunil Kushwaha
Runnisaidpur	JD(U)	Pankaj Kumar Mishra	RJD	Chandan Kumar
Belsand	LJP(RV)	Amit Kumar	RJD	Sanjay Gupta
Harlakhi	JD(U)	Sudhanshu Shekhar	CPI	Ram Naresh Pandey
Benipatti	BJP	Vinod Narayan Jha	INC	Nalini Ranjan Jha
Khajauli	BJP	Arun Shankar Prasad	RJD	Braj Kishore Yadav
Babubarhi	JD(U)	Mina Kumari	RJD	Arun Kushwaha
Bisfi	BJP	Haribhushan Thakur	RJD	Asif Ahmad
Madhubani	RLM	Madhav Anand	RJD	Samir Kumar Mahaseth
Rajnagar (SC)	BJP	Sujeet Paswan	RJD	Bishnudeo Mochi
Jhanjharpur	BJP	Nitish Mishra	CPI	Ram Narayan Yadav
Phulparas	JD(U)	Sheela Kumari	INC	Subodh Mandal
Laukaha	JD(U)	Satish Kumar Sah	RJD	Bharat Bhushan Mandal
Nirmali	JD(U)	Aniruddha Prasad Yadav	RJD	Baijnath Mehta
Pipra (Supaul)	JD(U)	Rambilash Kamat	CPI(ML)L	Anil Kumar
Supaul	JD(U)	Bijendra Prasad Yadav	INC	Minnat Rahmani
Triveniganj (SC)	JD(U)	Sonam Rani Sardar	RJD	Santosh Sardar
Chhatapur	BJP	Neeraj Kumar Singh Bablu	RJD	Dr. Vipin Kumar Nonia
Narpatganj	BJP	Devanti Yadav	RJD	Manish Yadav
Raniganj (SC)	JD(U)	Achmit Rishidev	RJD	Avinash Mangalam
Forbesganj	BJP	Vidya Sagar Keshri	INC	Manoj Vishwas
Araria	JD(U)	Shagufta Azim	INC	Avidur Rahman
Jokihat	JD(U)	Manzar Alam	RJD	Mohammed Shahnawaz Alam
Sikti	BJP	Vijay Kumar Mandal	VIP	Hari Narayan Pramanik
Bahadurganj	LJP(RV)	Mohammad Kalimuddin	INC	Maswar Alam
Thakurganj	JD(U)	Gopal Kumar Agarwal	RJD	Saud Alam
Kishanganj	BJP	Sweety Singh	INC	Qamrul Hoda
Kochadhaman	BJP	Bina Devi	RJD	Mujahid Alam
Amour	JD(U)	Sabir Ali	INC	Abdul Jalil Mastan
Baisi	BJP	Vinod Yadav	RJD	Abdus subhan

Kasba	LJP(RV)	Nitesh Kumar Singh	INC	Irfan Alam
Banmankhi (SC)	BJP	Krishna Kumar Rishi	INC	Devnarayan Rajak
Rupauli	JD(U)	Kaladhar Mandal	RJD	Bima Bharati
Dhamdaha	JD(U)	Leshi Singh	RJD	Santosh Kushwaha
Purnia	BJP	Vijay Kumar Khemka	INC	Jitender Yadav
Katihar	BJP	Tarkishore Prasad	VIP	Saurabh Agarwal
Kadwa	JD(U)	Dulal Chandra Goswami	INC	Shakeel Ahmad Khan
Balrampur	LJP(RV)	Sangita Devi	CPI(ML)L	Mahbub Alam
Pranpur	BJP	Nisha Singh	RJD	Ishrat parween
Manihari (ST)	JD(U)	Shambhu Suman	INC	Manohar Prasad Singh
Barari	JD(U)	Vijay Singh Nishad	INC	Tauquir Alam
Korha (SC)	BJP	Kavita Devi	INC	Punam Paswan
Alamnagar	JD(U)	Narendra Narayan Yadav	VIP	Nabin Kumar
Bihariganj	JD(U)	Niranjan Kumar Mehta	RJD	Renu Kushawaha
Singheshwar (SC)	JD(U)	Ramesh Rishidev	RJD	Chandrahas Chaupal
Madhepura	JD(U)	Kavita Kumari Saha	RJD	Chandrashekhar Yadav
Sonbarsha (SC)	JD(U)	Ratnesh Sada	INC	Sarita Devi
Saharsa	BJP	Alok Ranjan Jha	IIP	Indrajeet Prasad Gupta
Simri Bakhtiarpur	LJP(RV)	Sanjay Kumar Singh	RJD	Yusuf Salahuddin
Mahishi	JD(U)	Gunjeshwar Sah	RJD	Gautam Krishna
Kusheshwar Asthan (SC)	JD(U)	Atirek Kumar	Independent	Ganesh Bharti
Gaura Bauram	BJP	Sujit Kumar Singh	VIP	Santosh Sahani
			RJD	Afzal Ali Khan
Benipur	JD(U)	Binay Kumar Choudhary	INC	Mithilesh Kumar Chaudhary
Alinagar	BJP	Maithili Thakur	RJD	Binod Mishra
Darbhanga Rural	JD(U)	Ishwar Mandal	RJD	Lalit Kumar Yadav
Darbhanga	BJP	Sanjay Saraogi	VIP	Umesh Sahani
Hayaghat	BJP	Ram Chandra Prasad	CPI(M)	Shyam Bharati
Bahadurpur	JD(U)	Madan Sahni	RJD	Bhola Yadav
Keoti	BJP	Murari Mohan Jha	RJD	Faraz Fatmi
Jale	BJP	Jibesh Kumar Mishra	INC	Rishi Mishra
Gaighat	JD(U)	Komal Singh	RJD	Niranjan Ray
Aurai	BJP	Rama Nishad	VIP	Bhogendar Sahani
Minapur	JD(U)	Ajay Kushwaha	RJD	Munna Yadav
Bochahan (SC)	LJP(RV)	Baby Kumari	RJD	Amar Kumar Paswan
Sakra (SC)	JD(U)	Aditya Kumar	INC	Umesh Ram
Kurhani	BJP	Kedar Prasad Gupta	RJD	Sunil Kumar Suman
Muzaffarpur	BJP	Ranjan Kumar	INC	Bijendra Chaudhary
Kanti	JD(U)	Ajit Kumar	RJD	Mohammad Israil Mansuri
Baruraj	BJP	Arun Kumar Singh	VIP	Rakesh Kumar
Paroo	RLM	Madan Chaudhary	RJD	Shankar Prasad Yadav
Sahebganj	BJP	Raju Kumar Singh	RJD	Prithvinath Ray
Baikunthpur	BJP	Mithlesh Tiwari	RJD	Prem Shankar Prasad
Barauli	JD(U)	Manjeet Kumar Singh	RJD	Dilip Kumar Singh
Gopalganj	BJP	Subhash Singh	INC	Om Prakash Garg
Kuchaikote	JD(U)	Amrendra Kumar Pandey	INC	Hari Narain Kushwah
Bhore (SC)	JD(U)	Sunil Kumar	CPI(ML)L	Dhananjay Kumar
Hathua	JD(U)	Ramsewak Singh Kushwaha	RJD	Rajesh Singh Kushwaha
Siwan	BJP	Mangal Pandey	RJD	Awadh Bihari Choudhary
Ziradei	JD(U)	Bhism Pratap Singh	CPI(ML)L	Amarjeet Kushwaha
Darauli (SC)	LJP(RV)	Vishnu Deo Paswan	CPI(ML)L	Satyadeo Ram
Raghunathpur	JD(U)	Vikash Kumar Singh	RJD	Osama Shahab
Daraunda	BJP	Karanjeet Singh	CPI(ML)L	Amarnath Yadav
Barharia	JD(U)	Indradev Patel	RJD	Arun Kumar Gupta
Goriakothi	BJP	Devesh Kant Singh	RJD	Anwarul Haque
Maharajganj	JD(U)	Hemnarayan Sah	RJD	Vishal Jaiswal
Ekma	JD(U)	Manoranjan singh Dhumal	RJD	Srikant Yadav
Manjhi	JD(U)	Randhir Kumar Singh	CPI(M)	Satyendra Yadav

Baniapur	BJP	Kedar Nath Singh	RJD	Chandani Devi
Taraiya	BJP	Janak Singh	RJD	Shailendra Pratap
Marhaura	None		RJD	Jitendra Kumar Rai
Chapra	BJP	Chhoti Kumari	RJD	Khesari Lal Yadav
Garkha (SC)	LJP(RV)	Simant Mrinal	RJD	Surendra Ram
Amnour	BJP	Krishna Kumar Mantoo	RJD	Sunil Kumar
Parsa	JD(U)	Chhote Lal Ray	RJD	Karishma Rai
Sonpur	BJP	Vinay Kumar Singh	RJD	Ramanuj Prasad Yadav
Hajipur	BJP	Awadhesh Singh	RJD	Deo Kumar Chaurasia
Lalganj	BJP	Sanjay Kumar Singh	RJD	Shivani Shukla
Vaishali	JD(U)	Siddharth Patel	INC	Sanjeev Singh
			RJD	Ajay Kumar Kushwaha
Mahua	LJP(RV)	Sanjay Kumar Singh	RJD	Mukesh Kumar Raushan
Raja Pakar (SC)	JD(U)	Mahendra Ram	INC	Pratima Das
			CPI	Mohit Paswan
Raghopur	BJP	Satish Kumar Yadav	RJD	Tejashwi Yadav
Mahnar	JD(U)	Umesh Singh Kushwaha	RJD	Ravindra Kumar Singh
Patepur (SC)	BJP	Lakhendra Raushan	RJD	Prema Chaudhary
Kalyanpur (SC)	JD(U)	Maheshwar Hazari	CPI(ML)L	Ranjeet Ram
Warisnagar	JD(U)	Manjarik Mrinal	CPI(ML)L	Phoolbabu Singh
Samastipur	JD(U)	Ashwamedh Devi	RJD	Akhtarul Islam Shahin
Ujiarpur	RLM	Prashant Kumar Pankaj	RJD	Alok Kumar Mehta
Morwa	JD(U)	Vidya Sagar Singh Nishad	RJD	Ranvijay Sahu
Sarairanjan	JD(U)	Vijay Kumar Chaudhary	RJD	Arbind Kumar Sahani
Mohiuddinnagar	BJP	Rajesh Singh	RJD	Ejya Yadav
Bibhutipur	JD(U)	Raveena Kushwaha	CPI(M)	Ajay Kumar
Rosera (SC)	BJP	Birendra Paswan	INC	Braj Kishore Ravi
Hasanpur	JD(U)	Raj Kumar Ray	RJD	Mala Pushpam
Cheria-Bariarpur	JD(U)	Abhishek Kumar	RJD	Sushil Kumar
Bachhwara	BJP	Surendra Mehata	INC	Shiv Prakash Garib Das
			CPI	Abdesh Kumar Rai
Teghra	BJP	Rajnish Kumar Singh	CPI	Ram Ratan Singh
Matihani	JD(U)	Rajkumar Singh	RJD	Narendra Kumar Singh
Sahebpur Kamal	LJP(RV)	Surendra Kumar	RJD	Sattanand Sambuddha
Begusarai	BJP	Kundan Kumar	INC	Amita Bhushan
Bakhri (SC)	LJP(RV)	Sanjay Paswan	CPI	Suryakant Paswan
Alauli (SC)	JD(U)	Ram Chandra Sada	RJD	Ramvriksh Sada
Khagaria	JD(U)	Bablu Mandal	INC	Chandan Yadav
Beldaur	JD(U)	Panna Lal Singh Patel	INC	Mithilesh Kumar Nishad
			IIP	Tanisha Bharti
Parbatta	LJP(RV)	Aditya Kumar Shorya	RJD	Sanjeev Kumar
Bihpur	BJP	Kumar Shailendra	VIP	Aprana Kumari Mandal
Gopalpur	JD(U)	Shailesh Kumar Mandal	VIP	Prem Sagar
Pirpainti (SC)	BJP	Murari Paswan	RJD	Ram Vilas Paswan
Kahalgaon	JD(U)	Shubhanand Mukesh	RJD	Rajnish Bharti
			INC	Praveen Singh Kushwaha
Bhagalpur	BJP	Rohit Pandey	INC	Ajit Sharma
Sultanganj	JD(U)	Lalit Narayan Mandal	INC	Lalan Kumar
			RJD	Chandan Sinha
Nathnagar	LJP(RV)	Mithun Yadav	RJD	Sheikh Zeyaul Hassan
Amarpur	JD(U)	Jayant Raj Kushwaha	INC	Jitendra Singh
Dhoraiya (SC)	JD(U)	Manish Kumar	RJD	Tribhuvan Das
Banka	BJP	Ramnarayan Mandal	CPI	Sanjay Kumar
Katoria (ST)	BJP	Puran Lal Tudu	RJD	Sweety Sima Hembram
Belhar	JD(U)	Manoj Yadav	RJD	Chanakya Prakash Ranjan
Tarapur	BJP	Samrat Choudhary	RJD	Arun Kumar
Munger	BJP	Kumar Pranay	RJD	Avinash Kumar Vidyarthi
Jamalpur	JD(U)	Nachiketa Mandal	IIP	Narendra Kumar
Suryagarha	JD(U)	Ramanand Mandal	RJD	Premsagar Choudhary

Lakhisarai	BJ	Vijay Kumar Sinha	INC	Amresh Kumar Aneesh
Sheikhpura	JD(U)	Randhir Kumar Soni	RJD	Vijay Kumar
Barbigha	JD(U)	Kumar Pushpanjay	INC	Trishuldhari Singh
Asthawan	JD(U)	Jitendra Kumar	RJD	Ravi Ranjan Kumar
Bihar Sharif	BJP	Sunil Kumar	INC	Omair Khan
			CPI	Shiv Kumar Yadav
Rajgir (SC)	JD(U)	Kaushal Kishore	CPI(ML)L	Biswanath Choudhary
Islampur	JD(U)	Ruhel Ranjan	RJD	Rakesh Kumar Raushan
Hilsa	JD(U)	Krishnamurari Sharan	RJD	Shaki Singh Yadav
Nalanda	JD(U)	Shrawan Kumar	INC	Kaushlendra Kumar
Harnaut	JD(U)	Harinarayan Singh	INC	Arun Kumar Bind
Mokama	JD(U)	Anant Kumar Singh	RJD	Veena Devi
Barh	BJP	Siyaram Singh	RJD	Karnveer Singh Yadav
Bakhtiarpur	LJP(RV)	Arun Kumar	RJD	Aniruddh Kumar
Digha	BJP	Sanjiv Chaurasiya	CPI(ML)L	Divya Gautam
Bankipur	BJP	Nitin Nabin	RJD	Rekha Kumari
Kumhrar	BJP	Sanjay Gupta	INC	Indradeep Chandravanshi
Patna Sahib	BJP	Ratnesh Kushwaha	INC	Shashant Shekar
Fatuha	LJP(RV)	Roopa Kumari	RJD	Ramanand Yadav
Danapur	BJP	Ram Kripal Yadav	RJD	Rit Lal Ray
Maner	LJP(RV)	Jitendra Yadav	RJD	Bhai Virendra
Phulwari (SC)	JD(U)	Shyam Rajak	CPI(ML)L	Gopal Ravidas
Masaurhi (SC)	JD(U)	Arun Manjhi	RJD	Rekha Devi
Paliganj	LJP(RV)	Sunil Kumar	CPI(ML)L	Sandeep Saurav
Bikram	BJP	Siddharth Saurav	INC	Anil Kumar
Sandesh	JD(U)	Radha Charan Sah	RJD	Dipu Singh
Barhara	BJP	Raghvendra Pratap Singh	RJD	Ashok Kumar Singh
Arrah	BJP	Sanjay Singh Tiger	CPI(ML)L	Quyamuddin Ansar
Agiaon (SC)	BJP	Mahesh Paswan	CPI(ML)L	Shiv Prakash Ranjan
Tarari	BJP	Vishal Prashant	CPI(ML)L	Madan Singh Chandravanshi
Jagdishpur	JD(U)	Shri Bhagwan Singh Kushwaha	RJD	Kishore Kunal
Shahpur	BJP	Rakesh Ojha	RJD	Rahul Tiwary
Brahampur	LJP(RV)	Hulas Pandey	RJD	Shambhu Nath Yadav
Buxar	BJP	Anand Mishra	INC	Sanjay Kumar Tiwari
Dumraon	JD(U)	Rahul Singh	CPI(ML)L	Ajit Kushwaha
Rajpur (SC)	JD(U)	Santosh Kumar Nirala	INC	Vishwanath Ram
Ramgarh	BJP	Ashok Kumar Singh	RJD	Ajit Singh
Mohania (SC)	BJP	Sangita Kumari	Independent	Ravi Paswan
Bhabua	BJP	Bharat Bind	RJD	Birender Kushwaha
Chainpur	JD(U)	Mohd Zama Khan	VIP	Bal Govind Bind
			RJD	Brij Kishore Bind
Chenari (SC)	LJP(RV)	Murari Prasad Gautam	INC	Mangal Ram
Sasaram	RLM	Snehlata Kushwaha	RJD	Satender Sah
Kargahar	JD(U)	Bashisth Singh	INC	Santosh Kumar Mishra
			CPI	Mahendra Prasad Gupta
Dinara	RLM	Alok Kumar Singh	RJD	Rajesh Yadav
Nokha	JD(U)	Nagendra Chandravanshi	RJD	Anita Devi
Dehri	LJP(RV)	Rajeev Ranjan Singh	RJD	Guddu Chandravanshi
Karakat	JD(U)	Mahabali Singh	CPI(ML)L	Arun Singh Kushwaha
Arwal	BJP	Manoj Kumar	CPI(ML)L	Maha Nand Singh
Kurtha	JD(U)	Pappu Verma	RJD	Suday Yadav
Jehanabad	JD(U)	Chandeshwar Prasad	RJD	Rahul Sharma
Ghosi	JD(U)	Rituraj Kumar	CPI(ML)L	Ram Bali Singh Yadav
Makhdumpur (SC)	LJP(RV)	Rani Kumari	RJD	Subedar Das
Goh	BJP	Ranvijay Kumar	RJD	Amrender Kushwaha
Obra	LJP(RV)	Prakash Chandra	RJD	Rishi Kumar
Nabinagar	JD(U)	Chetan Anand	RJD	Amod Chandravanshi
Kutumba (SC)	HAM(S)	Lalan Ram	INC	Rajesh Ram

Aurangabad	BJP	Trivikram Singh	INC	Anand Shankar Singh
Rafiganj	JD(U)	Pramod Kumar Singh	RJD	Dr. Ghulam Shahid
Gurua	BJP	Upendra Dangi	RJD	Vinay Kumar
Sherghati	LJP(RV)	Uday Kumar Singh	RJD	Pramod Verma
Imamganj (SC)	HAM(S)	Deepa Manjhi	RJD	Ritu Priya Chaudhary
Barachatti (SC)	HAM(S)	Jyoti Devi	RJD	Tanushree Manjhi
Bodh Gaya (SC)	LJP(RV)	Shyam Deo Paswan	RJD	Kumar Sarvjit Paswan
Gaya Town	BJP	Prem Kumar	INC	Mohan Shrivasta
Tikari	HAM(S)	Anil Kumar	RJD	Ajay Dangi
Belaganj	JD(U)	Manorama Devi	RJD	Vishwanath Kumar Singh
Atri	HAM(S)	Romit Kumar	RJD	Vaijayanti Devi
Wazirganj	BJP	Birendra Singh	INC	Awadhesh Singh
Rajauli (SC)	LJP(RV)	Vimala Rajvanshi	RJD	Pinki Chaudhary
Hisua	BJP	Anil Singh	INC	Nitu Kumari
Nawada	JD(U)	Vibha Devi Yadav	RJD	Kaushal Yadav
Gobindpur	LJP(RV)	Binita Mahato	RJD	Purnima Devi
Warisaliganj	BJP	Aruna Devi	RJD	Anita Devi Mahato
Sikandra (SC)	HAM(S)	Prafull Manjhi	INC	Vinod Kumar Chaudhary
			RJD	Uday Narain Choudhary
Jamui	BJP	Shreyasi Singh	RJD	Shamshad Alam
Jhajha	JD(U)	Damodar Rawat	RJD	Jai Prakash Yadav
Chakai	JD(U)	Sumit Singh	RJD	Savitri Devi

का अखाड़ा योद्धाओं से सज गया है। नामांकन वापसी की समय सीमा (20 अक्तूबर) समाप्त होने के बाद अब 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार बच गए हैं। इनके बीच छह नवंबर को मुकाबला होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार, इन सीटों पर कुल 1690 उम्मीदवारों ने 2496 सेट में नामांकन दाखिल किया था। इनमें 315 नामांकन संवीक्षा के दौरान रद्द हुए, जबकि 61 उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया। दानापुर में निर्दलीय टिंकु कुमार यादव ने अपने भाई रीतलाल राय, डुमरांव में निर्दलीय करतार सिंह यादव ने अपने पिता ददन सिंह यादव और पटना साहिब में निर्दलीय शिशिर कुमार और डॉ. अजय प्रकाश ने भाजपा उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा के समर्थन में मैदान से हटे। नामांकन वापस लेने वाले अन्य उम्मीदवारों में बरौली से पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय, खगड़िया से रालोजपा उम्मीदवार रहीं पूर्व विधायक पूनम देवी यादव, बक्सर से निर्दलीय अमरेंद्र पांडेय, गोपालगंज से जनसुराज के शशिशेखर सिन्हा, ब्रह्मपुर से जनसुराज के सत्यप्रकाश तिवारी, रघुनाथपुर से बसपा के अवधेश भगत, बछवाड़ा से बसपा के दिलीप कुमार और सिंहेश्वर से आप के नंदन कुमार शामिल रहे। वहीं दानापुर से जनसुराज के प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं किया। सनद् रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 101 उम्मीदवारों की सूची में यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अनुभवी नेताओं के साथ-साथ इस बार नए चेहरे भी चुनावी मैदान में कमाल दिखाएंगे। जारी की गई सूची में कुल 15 उम्मीदवार ऐसे हैं, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इन उम्मीदवारों पर अपने क्षेत्र में

कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने राजनगर से युवा सुजीत पासवान को उतारा है। इस बार पार्टी ने अनुभवी रामप्रीत पासवान को आराम दिया है। गौरा बराम विधासनसभा से इस बार सुजीत सिंह को चुनावी जंग में उतारा है। ये पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेघरा विधानसभा से भी अनुभवी रजनीश कुमार को चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये भी पहले विधान परिषद में थे। इस बार अपनी किस्मत विधानसभा में भी आजमाएंगे। कटोरिया विधानसभा से भी बीजेपी के रणनीतिकारों ने एक नए उम्मीदवार पर भाग्य आजमाया है। यहां से पूरण लाल टुडू ताल ठोक रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा से विधायक रहे अरुण कुमार सिन्हा को पार्टी ने विराम दिया है। यहां से नए व सक्रिय कार्यकर्ता संजय गुप्ता पर बीजेपी के रणनीतिकारों ने बाजी खेली है। पटनासाहिब विधानसभा से इस बार विधानसभा अध्यक्ष रहे नंद किशोर यादव का टिकट काट कर युवा नेता रत्नेश कुशवाहा को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। रत्नेश कुशवाहा के लिए यह पहला मौका है जब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी सौंपी है। औरंगाबाद विधानसभा से इस बार बीजेपी के रणनीतिकारों ने नए उम्मीदवार को मौका दिया है। यहां से पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह को चुनावी जंग में उतारा है। ये उनकी पहली चुनावी जंग है। बीजेपी ने अलीनगर विधानसभा से मैथिली की जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर को चुनावी जंग में उतारा है। यहां से वीआईपी के मिश्री लाला यादव विधायक थे। ये फिर बीजेपी में आ गए। फिलहाल बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा से बीजेपी ने इस बार नए चेहरे पर विश्वास किया है। मुजफ्फरपुर से इस बार रंजन कुमार चुनाव लड़ेंगे। यहां से पहले सुरेश शर्मा चुनाव लड़ते रहे हैं। पहले मंत्री भी थे। पर वर्ष 2020 के चुनाव में कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी से हार गए थे। छपरा विधानसभा से सी.एन. गुप्ता विधायक थे। ये 70 प्लस नेताओं में शामिल थे। इनका टिकट काट बीजेपी ने युवा रंजन कुमार को चुनावी जंग में उतारा है। बाढ़ विधानसभा से बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक थे। इन पर पार्टी विरोधी बयान देने का आरोप था। उनका भी टिकट काटकर यहां से चर्चित चिकित्सक डॉ. सियाराम सिंह को चुनावी जंग में उतारा है। अंगियाव विधानसभा से बीजेपी ने नया चेहरा महेश पासवान को उतारा है। यहां से जदयू चुनाव

हार गई थी। यहां से मनोज मंजिल (माले) के विधायक थे। जेडीयू से यह सीट बीजेपी ने ले ली है। रामनगर विधासनसभा से बीजेपी ने इस बार नन्द किशोर राम को उतारा है। यहां से बीजेपी की भागीरथी देवी विधायक थी। इनपर शक्ति परीक्षण के दौरान राजद की तरफ होने का आरोप लगा था। नरकटियागंज से बीजेपी ने इस बार संजय पासवान को उतारा है। यहां से रश्मि वर्मा बीजेपी की विधायक थीं, पर शक्ति परीक्षण के दौरान इन पर आरोप लगा था कि ये राजद की तरफ वोटिंग करने वाली थी। इस वजह से रश्मि वर्मा का टिकट कट गया। कोचाधामन से बीजेपी ने वीणा देवी को उतारा है। यह सीट जदयू की थी। पिछली बार एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने यह सीट जदयू से ले लिया। बीजेपी ने पीरपैंती विधानसभा से इस बार नए चेहरे को जगह दी है। यहां से इस बार मुरारी पासवान को टिकट मिला है।

बहरहाल, बीजेपी ने अब तक कुल 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा ने जीत की उम्मीद में कुछ नए चेहरे उतारे तो कुछ पुराने और अनुभवी नेताओं को इस बार विराम भी दिया है। पार्टी में बदलाव की बयार ने 18 दिग्गजों को ही बेटिकट कर दिया। बीजेपी ने इस बार एक बड़ा निर्णय करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट ही काट दिया। कई बार के विधायक रहे और कई भूमिका का निर्वहन करने वाले नंदकिशोर यादव को इस बार विराम दिया गया। ये मंत्री भी रहे, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष भी रहे। वही अरुण सिन्हा कुम्हरार से करीब 20 वर्षों से विधायक रहे हैं। बीजेपी के प्रारंभ से ही नेता रहे। ये काफी मिलनसार रहने के कारण ये जनता के बीच लोकप्रिय भी रहे। पार्टी के सचेतक भी रहे, पर उम्र की आड़ में इनका टिकट काट दिया गया। वही आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह सीटिंग विधायक थे। उम्र के कारण इनका भी टिकट कटा। ये कृषि मंत्री भी रहे। बीजेपी ने इस बार युवा नेता संजय टाइगर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने औराई से पूर्व मंत्री रामसूरत राय को चुनावी जंग से बाहर किया। इन पर सरकार में मंत्री रहने के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नीतीश की नजर टेढ़ी हो गई थी। तब भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की उस वक्त की गई सारी ट्रांसफर-पोस्टिंग रद्द कर दी गई थी। अब औराई सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काट दिया। उनकी जगह रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया है। रीगा से मोतीलाल प्रसाद की जगह बैद्यनाथ प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। मोतीलाल प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पर इन पर एंटी इन्कंबेंसी और कार्य की दक्षता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। वही बीजेपी ने अलीनगर से मिश्रीलाल यादव की जगह मैथिली ठाकुर को और गौड़ा बौराम से स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार की जगह सुनील पिंटू को उम्मीदवारी दी गई है। ये 2019 के चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने। बीजेपी ने राजनगर सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान की जगह सुजीत पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। नरपतगंज से मौजूदा विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काटकर देवंती यादव पर भरोसा जताया गया है। कटोरिया सुरक्षित सीट से पार्टी ने निक्की हेंब्रम का टिकट काटकर पूरनलाल टुडू को उम्मीदवार बनाया है। उनकी जगह पार्टी ने अब युवा उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मुंगेर से विधायक प्रणव कुमार का टिकट काटकर पार्टी ने कुमार प्रणय को उम्मीदवार बनाया। बाढ़ से ज्ञानेंद्र ज्ञानू का टिकट काट कर डॉ सियाराम सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। छपरा से विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। गोपालगंज से विधायक कुसुम देवी का टिकट काट कर सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया गया।

कहते हैं सियासत में परिवारवाद पर जितने हमले हुए, इसकी जड़ें उतनी मजबूत होती चली गईं। हाल के चुनावों में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन नेताओं ने परिजनों को टिकट से नवाजने में अपनी ताकत झोंकी और ज्यादातर कामयाब भी रहे। किसी भी दल ने अपने नुमाइंदों को मायूस नहीं किया। बिहार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के साथ ही राजनीतिक घरानों के सदस्यों का नाम भी खुलकर सामने आ रहा है। नेताओं के पुत्र, पिता और पत्नी को टिकट देने में कोई दल पीछे नहीं है। कई राजनेता खुद की बजाए अपने बेटे या पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। राजद ने संदेश की विधायक किरण देवी की जगह उनके बेटे दीपू सिंह को सिंबल दिया है, तो भाजपा ने गौराबौराम से विधायक स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व सांसद अजय निषाद ने लोकसभा चुनाव में बेटिकट होने के बाद भाजपा से इस्तीफा दिया था। पुनः यह वापस भाजपा में लौटे। उनकी पत्नी रमा निषाद औराई से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉ अशोक राम हाल ही जदयू में शामिल हुए थे। उनके बेटे अतिरेक को कुशेश्वरस्थान से सिंबल मिला है। भाजपा ने पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह को औरंगाबाद से टिकट दिया है। जमुई से श्रेयसी सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री को फिर से टिकट दिया है, रालोमो

प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से एनडीए की उम्मीदवार हैं। लोजपा (आर) प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से सांसद हैं। इस बार चिराग के भांजे सीमांत मृणाल को गरखा से टिकट मिला है। उधर, रघुनाथपुर से मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बेटिकट कर सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को उतारा गया है। रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पहली बार अलौली से चुनाव लड़ेंगे। वही हम को एनडीए में मिली छह सीटों में से चार पर राजनीतिक परिवार के लोग प्रत्याशी बनाये गये हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा इमामगंज और समधन ज्योति देवी बाराचट्टी से प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार के भतीजे रोमित कुमार अतरी से भाई अनिल कुमार (विधायक) टिकारी से प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद के तीन परिजन मैदान में होंगे। अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज घोषी से जदयू प्रत्याशी बनाए गये हैं। वही पहली बार बिहार की सियासत में दावेदारी पेश कर रही जनसुराज ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता को अस्थावां से मैदान में उतारा है। भाकपा के पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय के पुत्र राकेश पांडेय हरलाखी से पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। बसपा ने करगहर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के बेटे उदय कुमार को उतारा है। वही जदयू में भी पहली बार कई राजनीतिक परिवारों के लोग मैदान में उतारे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह के भाई राहुल सिंह को डुमरांव से टिकट मिला है। गायघाट से लोजपा (आर) सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल और मीनापुर से पूर्व विधायक दिनेश कुशवाहा के पुत्र अजय सहनी को सिंबल मिला है। सकरा से अशोक कुमार चौधरी के बेटे आदित्य कुमार, सिकटा से पूर्व भाजपा विधायक दिलीप वर्मा के बेटे समृद्ध वर्मा और इस्लामपुर से स्व. राजीव रंजन के बेटे रुहेल रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। नवीनगर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को जदयू ने टिकट दिया है। वही भाजपा की पहली सूची में 11 नाम ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इनमें बड़हरा से राघवेन्द्र प्रताप सिंह जो कि पूर्व मंत्री अंबिका शरण के बेटे हैं, झंझारपुर से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जो कि पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के बेटे, बरुराज से अरुण सिंह, जो कि पूर्व विधायक बृज किशोर सिंह के पुत्र, बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, जो कि नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र, दीघा से संजीव चौरसिया, जो कि पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया के बेटे हैं को टिकट मिला है। शामिल हैं। इसी तरह मधुबन से प्रत्याशी राणा रणधीर के पिता सीताराम सिंह राजद सरकार में मंत्री और सांसद रहे थे। वही राजद के उम्मीदवारों में परिवारवाद का बोलबाला है। बेलागंज से पिछली बार सुरेन्द्र यादव चुनाव जीते थे। पिछले साल वे सांसद बन गए। उपचुनाव में उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वे हार गए थे। इस बार भी राजद ने विश्वनाथ यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। मुंगेर से प्रत्याशी मुकेश यादव जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली अर्चना कुमारी के पति हैं। रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे ओसामा साहेब सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। हसनपुर से माला पुष्पम चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति सुनील कुमार पुष्पम कई बार के विधायक रह चुके हैं। बनियापुर से चुनाव लड़ रहीं चांदनी सिंह पूर्व विधायक अशोक सिंह की पत्नी हैं। संदेश की मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव को राजद ने टिकट दिया है। तेजस्वी यादव जो कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद के पुत्र हैं और राघोपुर सीट से हैं। वही हाल ही में राजद में

शामिल हुए पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को जहानाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। विजय प्रकाश जो कि पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के भाई हैं जिन्हे जमुई से राजद लड़ा रही है। राहुल तिवारी, पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं और राजद इन्हें शाहपुर से लड़ा रही है। आलोक मेहता, पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता के बेटे हैं ये भी उजियारपुर से राजद की टिकट पर हैं, समीर कुमार महासेठ, पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ के पुत्र, हैं मधुबनी से राजद से हैं। इनके साथ ही और भी कई ऐसे नाम हैं जिनके लिए नेताओं ने परिजनों को टिकट से नवाजने में अपनी ताकत झोंकी है।

बहरहाल, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक एलान हुए बिना ही राजद ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया था, जिनमें 84 से अधिक उम्मीदवारों को पार्टी ने सिम्बल दे भी दिया था। इनमें कुछ ऐसी भी सीटें हैं, जहां से पिछली बार महागठबंधन के अन्य घटक दल चुनावी मैदान में उतरा था। टिकट वितरण में एम-वाई को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही अधिक भरोसा किया है। 22 मौजूदा विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दो सीट पर विधायक के बेटे चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाने के लिए मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बे-टिकट कर दिया गया है। हाल ही में राजद का दामन थामने वाले परबत्ता विधायक डॉ. संजीव को उम्मीदवार बनाया गया है। बोचहां से पिछली बार रमई राम चुनाव लड़े थे। इस बार अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार पारू कांग्रेस के कोटे में था। इस बार राजद ने शंकर यादव को उम्मीदवार बनाया है। शंकर पिछली बार पारू से निर्दलीय लड़े थे। राजद से वे पहली बार चुनाव लड़ेंगे। मुंगेर से मुकेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार अविनाश कुमार विद्यार्थी लड़े थे। हसनपुर से लालू प्रसाद के बड़े बेटे चुनावी मैदान में थे। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद इस बार राजद ने माला पुष्पम को उम्मीदवार बनाया है। बनियापुर से चांदनी सिंह तो संदेश से दीपू यादव पहली बार चुनावी मैदान में हैं। वही महागठबंधन में पहले से छः दल आपस में टिकट को लेकर उलझन में फंसे रहे, ऐसे में एक और सातवें दल का शामिल होना दिलचस्प है। इस पार्टी का नाम है आईआईपी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी दलों के महागठबंधन में 7वें दल की एंट्री हो गई है। पान समाज (तांती, ततवा जाति) की राजनीति करने वाले आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को महागठबंधन में 3 सीटें मिली है, जिनमें आईपी गुप्ता खुद सहरसा सीट से अपनी पार्टी के करनी छाप चुनाव चिह्न पर लड़ें रहे हैं। बता दें कि अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई थी। इसी साल अप्रैल महीने में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में पान समाज की बड़ी रैली करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों के अनुसार तांती-ततवा जाति के लोगों की आबादी लगभग 2 प्रतिशत है। ऐसे में कम मार्जिन से हार-जीत वाली सीटों पर पान समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। बता दें कि महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई-माले, सीपीएम, सीपीआई और मुकेश सहनी की वीआईपी को मिलाकर 6 पार्टियां पहले से है। आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आने से कुल 7 दल हो गए हैं। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई और 25 सीटों पर अलग से अपने प्रत्याशी उतार दिए।

गौरतलब है कि महागठबंधन के सभी घटक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में कोर वोट बैंक का पूरा ख्याल रखा है। सभी घटक दलों को मिलाकर देखें तो गठबंधन में पिछड़ा-अतिपिछड़ा को अधिक भागीदारी मिली है। कुल 255 उम्मीदवारों में 56 फीसदी उम्मीदवार पिछड़े हैं। इनमें भी एमवाई (मुस्लिम-यादव) की संख्या अधिक है। महागठबंधन में सबसे अधिक 67 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि 30 मुस्लिमों को भी टिकट दिया गया है। 30 कुर्मी-कुशवाहा तो 33 ईबीसी को उम्मीदवार बनाया

गया है। दलित और सवर्ण वर्ग से 41-41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। 13 वैश्य को भी महागठबंधन ने चुनावी मैदान में उतारा है। दलवार देखें तो राजद ने जहां एक तिहाई से अधिक उम्मीदवार केवल यादवों को बनाया है तो 18 मुस्लिमों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने एक तिहाई से अधिक सवर्णों को उम्मीदवार बनाया है। वीआईपी ने अतिपिछड़ों पर अधिक भरोसा किया है। वामदल में सबसे अधिक दलित और यादव उम्मीदवार हैं। राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इनमें 50 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि 18 मुस्लिम हैं। सत्ताधारी दल के वोट में सेंध लगाने के लिए राजद ने 18 कुर्मी और कुशवाहा को भी उम्मीदवार बनाया है। आठ वैश्य तो 14 सवर्ण उम्मीदवार बनाए गए हैं। सवर्ण में छह भूमिहार, पांच राजपूत और तीन ब्राह्मण हैं। 19 दलितों को भी राजद ने उतारा है। ये सभी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के एक तिहाई से अधिक उम्मीदवार सवर्ण वर्ग से हैं। इनमें भूमिहार आठ, राजपूत पांच, ब्राह्मण सात और एक कायस्थ हैं। पार्टी ने 10 मुस्लिमों को भी टिकट दिया है। पांच यादव, चार कुर्मी-कुशवाहा, छह ईबीसी, तीन वैश्य तो 12 दलित चुनावी मैदान में हैं। वामदल 33 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक दलित और यादव नौ-नौ उम्मीदवार हैं। सात कुर्मी और कुशवाहा तो एक ईबीसी को टिकट मिला है। दो वैश्य और तीन सवर्णों को टिकट मिला है। वहीं वीआईपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वीआईपी ने अतिपिछड़ों को अधिक भरोसा किया है। आठ उम्मीदवार ईबीसी हैं। वीआईपी से तीन यादव, एक कुर्मी/कुशवाहा, दो सवर्ण तो एक दलित भी चुनावी मैदान में हैं। इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (आईआईपी) तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके दो उम्मीदवार ईबीसी तो एक सवर्ण हैं। हालांकि कुछेक उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी की यह उम्मीदवारों की घोषणा नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया संदेश देने की कोशिश प्रतीत हो रही है। पार्टी ने इसमें अपने पारंपरिक यादव-मुस्लिम (माय) समीकरण को कायम रखते हुए युवाओं, महिलाओं और लोकप्रिय चेहरों को भी स्थान देकर सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है। राघोपुर से तेजस्वी यादव के फिर से मैदान में उतरने ने पार्टी की जड़ों को मजबूती दी है, वहीं खेसारी लाल यादव जैसे चर्चित चेहरे को टिकट देकर आरजेडी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह अब सिर्फ जातीय राजनीति नहीं, बल्कि जन-भावनाओं और स्टार फेस की अपील के सहारे भी मतदाताओं तक पहुंचना चाहती है। आरजेडी ने जातिगत संतुलन और स्टार अपील से एक साहसिक दांव चला है जो बिहार की पिछड़ी राजनीति को साधने का प्रयास है, लेकिन गठबंधन की कमजोरी और विवादास्पद चेहरों ने इसे जोखिम भरा बना दिया है। वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव के दोबारा मैदान में उतरने की पूरी संभावना थी और वही हुआ। वह नामांकन के अंतिम तारीख के एक दिन पहले ही नामांकन भी कर चुके थे, लेकिन राजद की लिस्ट में उनका नाम आना एक खास प्लान का हिस्सा कहा जा रहा है। जानकारों की नजर में यह निर्णय पार्टी के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों है। लिस्ट में नाम जोड़कर यह साबित करने की पूरी कोशिश है कि यह सीट आरजेडी की राजनीतिक परंपरा का केंद्र रही है। एक बार फिर से तेजस्वी का यहां से उतरना इस संदेश को और स्पष्ट करता है कि वे अब भी यादव-मुस्लिम समीकरण के साथ-साथ परंपरागत आधार को एकजुट रखने में भरोसा रखते हैं। यह कदम उनके नेतृत्व को स्थिरता और निरंतरता देने का संकेत भी देता है। वही सूची में सबसे बड़ा और अप्रत्याशित नाम भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का है, जिन्हें छपरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी का यह कदम एक साथ कई संकेत देता है। पहला, पार्टी युवाओं और मनोरंजन जगत की लोकप्रिय हस्तियों को शामिल कर चुनावी जमीन को विस्तारित करना चाहती है। दूसरा, खेसारी यादव जैसे बड़े चेहरे को टिकट देकर आरजेडी ने भाजपा के स्टार पावर के मुकाबले अपनी स्टार अपील को बढ़ाने की कोशिश की है। तीसरा, छपरा जैसी रणनीतिक सीट पर यह फैसला पार्टी की उस कोशिश को बता रहा है जिसमें वह पारंपरिक जातिगत सीमाओं से आगे बढ़कर भावनात्मक और लोकप्रिय अपील के जरिए नए मतदाताओं को साधना चाहती है। इसके साथ ही सूची में भाई वीरेंद्र (मनेर), भोला यादव (बहादुरपुर), प्रो. चंद्रशेखर (मधेपुरा), अवध बिहारी चौधरी (सीवान), अख्तरुल इस्लाम शाहीन (समस्तीपुर) जैसे नाम पार्टी की स्थिरता और संगठनात्मक अनुभव को बताते हैं। तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट किया है कि पार्टी केवल नए चेहरों पर निर्भर नहीं है; बल्कि पुराने नेताओं के अनुभव को भी सम्मान देती है। जाहिर है यह राजद की आंतरिक एकजुटता का संकेत है और पार्टी नेताओं को सीधा संदेश भी है।

बता दें कि आरजेडी की पहचान हमेशा सामाजिक न्याय की राजनीति से रही है। इस सूची में यादव, पासवान, कुशवाहा, मुसलमान, सवर्ण और दलित समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। यादव समुदाय से कई प्रत्याशी तेजस्वी यादव, मुन्ना यादव, प्रेम शंकर यादव, भाई वीरेंद्र जैसे नाम हैं जो पारंपरिक वोट बैंक को सहेजते हैं। दूसरी ओर, मुस्लिम चेहरों में मोहम्मद शाहनवाज (जोकीहाट), युसुफ सलाहउद्दीन (सिमरी बख्तियारपुर), मो. नेहालुद्दीन (रफीगंज) शामिल हैं जो मुस्लिम वोट को आकर्षित करने का प्रयास हैं। दलित और महादलित वर्ग से रामवृक्ष सदा (अलौली), चंद्रहास चौपाल (सिंहेश्वर) जैसे उम्मीदवार शामिल हैं, जिससे सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत को जीवित रखने की कोशिश की गई है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आरजेडी की इस सूची में कई चूकें साफ नजर आ रही हैं जो पार्टी की कमजोरियां उजागर करती हैं। सबसे बड़ा खतरा है महागठबंधन की आंतरिक कलह। कांग्रेस और आरजेडी ने विलंब से लिस्ट जारी की, जिससे वैशाली, लालगंज जैसी 7 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने-सामने आ गए। दूसरी चूक है विवादास्पद चेहरों का चयन। ओसामा शहाब का टिकट मुस्लिम वोट तो साध सकता है, लेकिन भाजपा इसे 'शहाबुद्दीन का वारिस' और 'जंगलराज का प्रतीक' बताकर सियासी हमले करेगी। इसी तरह, खेसारी लाल का सेलिब्रिटी स्टेटस ग्रामीण वोटरों को लुभा सकता है, लेकिन शहरी-मध्यम वर्ग में 'गंभीरता की कमी' का आरोप लगेगा। वही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों में ईबीसी समाज पर कम फोकस किया, जबकि जदयू ने अपनी लिस्ट में 57 नामों में इन्हें प्राथमिकता दी। इसके

अतिरिक्त सूची में कुछ महिला उम्मीदवार जैसे अनीता कुमारी (नोखा), माला पुष्पम (हसनपुर), चांदनी सिंह (बनियापुर), रेखा पासवान (मसौढ़ी) जरूर हैं, लेकिन कुल अनुपात के लिहाज से यह संख्या बहुत कम है। बिहार की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से आरजेडी ने यह मौका कुछ हद तक गंवाया है। यह विपक्षी दलों के लिए आलोचना का बिंदु बन सकता है। हालांकि, सूची में कई नए और अपेक्षाकृत युवा चेहरे शामिल हैं। राहुल तिवारी (शाहपुर), रणविजय साहू (मोरवा), आलोक मेहता (उजियारपुर) जैसे युवा चेहरों से संकेत मिलता है कि पार्टी संगठन को युवा दिशा देना चाहती है। बता दें कि तेजस्वी यादव स्वयं नई पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं और इस चुनाव को 'नई सोच, नया बिहार' की अवधारणा पर केंद्रित करना चाहते हैं। इस सूची के जरिए आरजेडी ने यह राजनीतिक संदेश दिया है कि वह केवल जातीय समीकरणों पर नहीं, बल्कि लोकप्रियता, युवाशक्ति और सामाजिक विविधता के संगम पर दांव लगा रही है। यह रणनीति बताती है कि पार्टी अब पुराने 'एमवाई' समीकरण से आगे बढ़कर व्यापक गठजोड़ की दिशा में सोच रही है। फिर भी, आरजेडी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं।

बहरहाल, बिहार में पारी और बारी की बेचैनी से इस बार बगावत की आंधी ने सियासी दलों, खासकर चार दर्जन सीटों पर अधिकृत उम्मीदवारों की नींद हराम कर दी है। बागियों को मनाने का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई नाराज नेताओं को मना कर पार्टी के मोर्चे पर खड़ा भी कर दिया। बावजूद भाजपा को भी कई सीटों पर बागियों से जूझना पड़ रहा है। जदयू, राजद, कांग्रेस और हम के भी अनेक बागी अखाड़े में इन पार्टियों के अधिकृत उम्मीदवारों को ललकार रहे हैं। संबंधित पार्टियां इन्हें मनाने में नाकाम होने पर निष्कासन का डंडा भी चला रही है। लेकिन, कितने बागी अपने दल का गणित बिगाड़ पाएंगे, यह कहना जल्दीबाजी होगी। बिहार में बागियों से दल परेशान हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर सभी प्रमुख दलों के तपे-तपाए नेता अपने बल पर (निर्दलीय) चुनावी मैदान में कूद गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। वे लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। कुछ तो अपने ही दल के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो सकता है। दल से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पहलवान किसी के लिए घातक तो विरोधियों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। मान-मनौव्वल के बाद भाजपा के कुछेक नेताओं ने नामांकन वापस ले लिया पर बाकी दल के लड़ाके अभी भी चुनावी अखाड़े में डटे हुए हैं। ऐसे नेताओं को छह साल तक के लिए निष्कासित किया गया है। चेतावनी भी दी गई है बैनर का इस्तेमाल किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही राजद ने 27 बागियों को दल से निष्कासित किया है। इसमें एक विधायक छोटे लाल राय जदयू के टिकट पर परसा से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि तीन नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। विधायक मो. कामरान गोविंदपुर से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। वहीं महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष रितू जायसवाल परिहार से, सरोज

यादव बड़हरा से, राजीव रंजन उर्फ पिंकु भइया जगदीशपुर से, अनिल यादव नरपतगंज से, अक्षय लाल यादव चिरैया से, रामसखा महतो चेरिया बरियारपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भगत यादव शेरघाटी से, मुकेश यादव संदेश से, संजय राय महनार से, कुमार गौरव और राजीव कुशवाहा दरभंगा से, महेश प्रसाद गुप्ता जाले से, पूनम देवी गुप्ता मोतिहारी से, सुरेन्द्र प्रसाद यादव सोनपुर से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। डॉ. राम प्रकाश महतो कटिहार से, प्रणव प्रकाश मधेपुरा से, अफजल अली गौड़ाबौराम से चुनाव लड़ रहे हैं। वही हम ने दल और एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ काम कर रहे 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। इन नेताओं में छह नेता बतौर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में हैं। इसमें राजेश रंजन घोसी से, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जहानाबाद से, नंदलाल मांझी बोध गया से, चंदन ठाकुर समस्तीपुर से, बीके सिंह मैरवा से और राजेन्द्र यादव कस्बा से निर्दलीय चुनावी मैदान में डटे हैं। लोजपा (आर) के रविशंकर प्रसाद और अशोक सूर्यगढ़ा से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं।

बताते चले कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पहले हुए अन्य चुनावों से काफी दिलचस्प और सभी दलों के लिए कांटो भरा है। हालात ऐसे हैं कि सिटिंग विधायक जिन्हें टिकट नहीं मिला, वह निर्दलीय मैदान में हैं और अगर उनकी जीत सुनिश्चित होती है तो सरकार किस दल की बन पायेगी या बहुमत पूर्ण होगा कह पाना मुश्किल है। अब तो यही कहेंगे कि बिहार में चुनावी रण सज चुका है और एनडीए ने अब अपनी स्पेशल वार प्लान टेबल पर रख दी है। जिन आठ जिलों में पिछली बार उसका खाता तक नहीं खुला था, अब वहीं से जीत की नई कहानी लिखने की तैयारी है। दूसरी ओर सुपौल जो एनडीए का शत-प्रतिशत जिला रहा है वहां पिछली जीत दोहराना भी किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं। मगर महागठबंधन ने भी पूरा जोर लगा दिया है। पटना से लेकर शिवहर तक और किशनगंज से लेकर औरंगाबाद तक, एनडीए ने बिहार के नौ जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर फोकस करते हुए विशेष रणनीति बनाई है। इन जिलों में जदयू, भाजपा, लोजपा (आर), रालोमो और हम सभी पांच घटक दलों ने मिलकर एक साझा मैदान रणनीति तैयार की है। केन्द्रीय नेतृत्व ने हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को अलग-अलग

जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अब ये अध्यक्ष जमीनी निगरानी कर रहे हैं, ताकि बूथ स्तर तक समन्वय बना रहे और कहीं भी संवादहीनता न हो। ज्ञात हो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शिवहर, किशनगंज, बक्सर, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जहानाबाद जिलों की 31 सीटों पर एक भी जीत नहीं मिली थी। इनमें से 28 सीटें महागठबंधन ने झटकी थीं, जबकि तीन सीटें तीसरे मोर्चे के खाते में चली गई। अब एनडीए इन इलाकों में हार को सीख मानकर नए समीकरण बिठाने में जुटा है। वही सुपौल जिला इस बार एनडीए के लिए टेस्ट जोन बना है। 2020 में एनडीए ने यहां की सभी पांच सीटें जीती थीं, यानी सौ फीसदी सफलता मिली थी। इस बार उसी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। गठबंधन ने सुपौल में संयुक्त जमीनी टीम बनाई है, जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक को घर-घर संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। उधर, महागठबंधन भी एनडीए के इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय मोड में डाल दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि एनडीए के आत्मविश्वास में ही उसकी ढिलाई छिपी है। किन्तु एनडीए नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि किसी स्तर पर संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि सभी प्रदेश उपाध्यक्षों और महासचिवों को मैदान में उतारा गया है। हर वोटर तक सीधा संपर्क और हर बूथ पर एक्टिव प्रकोष्ठ बनाने की मुहिम जारी है। राजनीतिक नतीजा जो भी हो, बिहार का यह चुनावी अध्याय

साफ बताता है कि इस बार एनडीए रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरा है। वहीं महागठबंधन ने भी पूरी फील्डिंग सजा दी है।

गौरतलब है कि 11 विधानसभा सीटों पर राजद, कांग्रेस समेत अन्य दलों के कैंडिडेट के बीच फ्रेंडली फाइट (दोस्ताना संघर्ष) होना तय है। इनमें से 5 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने- सामने होंगे। महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता के दौरान इस संबंध में पूछे गए सवाल पर सीपीआई माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ सीटों पर आपस में रणनीतिक मुकाबला होगा। एक-दो प्रतिशत इधर-उधर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, एक-दो प्रत्याशी का पीछे हटना चाहिए। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आगामी बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस में 5, कांग्रेस और सीपीआई में 4, राजद और वीआईपी में एक, कांग्रेस और आईआईपी में एक सीट पर आपसी मुकाबला होगा। यानी सबसे ज्यादा कांग्रेस को 9 सीटों पर सहयोगी दलों से ही मुकाबला करना होगा। वही पत्रकारों से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद कोई बड़ी बात नहीं है। 243 सीटें हैं उनमें 5-6 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं। लोकल परिस्थितियां होती हैं, फ्रेंडली फाइट मानी जाती है। इसे बहुत बड़े रूप में नहीं देखना चाहिए। गहलोत ने कहा कि इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस नेताओं के अनुसार जिन विधानसभा क्षेत्रों में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं, उनमें नरकटियागंज, वैशाली, राजापाकर, रोसड़ा, बछवाड़ा, कहलगांव, बिहारशरीफ, करगहर, गौड़ाबोराम, चैनपुर और सिकंदरा शामिल हैं।

बताते चले कि मतदान तारिखों की नजदीकियों के बीच एनडीए और महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सनद् रहे कि महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि सबका ध्यान रखते हुए यह घोषणा पत्र तैयार हुआ है। महागठबंधन ने कहा कि यह तेजस्वी की प्रतिज्ञा पत्र है। बता दें कि 'तेजस्वी प्रण पत्र' में कई लोक-लुभावन और महत्वाकांक्षी वादे शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सीधे तौर पर राज्य के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को लक्षित करना है। इस घोषणा पत्र का सबसे बड़ा और चर्चित वादा हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का है। यह वादा युवाओं के बीच बड़ा प्रभाव डाल सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की गई है। तेजस्वी यादव की खास 'माई-बहिन योजना' को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका विवरण जल्द ही सामने आएगा। इसके अलावा, राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक देने का वादा भी किया गया है। सनद् रहे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव को आखिरकार सीएम फेस घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मुखिया मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया है। कांग्रेस के वरीय नेता अशोक गहलोत ने इंडिया अलायंस की पटना में हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। बीते कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से परहेज कर रही थी। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता तेजस्वी के सीएम फेस के सवाल को मीडिया के सामने टालते रहे। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद, कांग्रेस और अन्य घटक दलों के बीच सहमति और असहमति का भी लंबा दौर चला। अंदरखाने से खबरें आई कि कांग्रेस चुनाव रिजल्ट के बाद ही मुख्यमंत्री का चुनाव चाहती है। किन्तु राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरीय नेता अशोक गहलोत ने पार्टी की ओर से बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष को बिहार चुनाव में महागठबंधन का सीएम फेस घोषित करते हुए कहा, "तेजस्वी ने पिछली बार भी कमाल किया था। मगर मामूली वोटों के अंतर से उनकी सरकार बनते हुए

रह गई थी।" अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया की ओर से बार-बार सीएम फेस के बारे में सवाल किया जा रहा था, इसलिए आज घोषणा करनी पड़ी। दरअसल, कांग्रेस अब तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस मानने से बचती रही। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से जब तेजस्वी पर सवाल किया था, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु समेत अन्य शीर्ष नेताओं ने भी बार-बार तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के सवाल को टाला था। बिहार चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के नामांकन के दौरान महागठबंधन की कलह खुलकर सामने आ गई थी। कुछ सीटों पर घटक दलों ने एक-दूसरे के सामने ही उम्मीदवार उतारकर दोस्ताना संघर्ष बना दिया। सुल्तानगंज, कहलगंव, वैशाली समेत कुछ सीटों पर कांग्रेस और राजद दोनों के उम्मीदवारों के नामांकन कर दिया। कांग्रेस ने बछवाड़ा और अन्य जगह पर लेफ्ट पार्टी सीपीआई के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी उतारा। इस वजह से महागठबंधन में गांठ उलझती नजर आई। खासकर राजद और कांग्रेस के बीच सीटों पर तनातनी बढ़ने के बाद अशोक गहलोत को सुलह के लिए पटना भेजा गया। गहलोत ने पटना आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से मुलाकात की। हालांकि, इस मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने कुछ खास नहीं बोला और कहा कि महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि महगठबंधन में उलझी हुई गांठ को अब सुलझा दिया गया है। कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के साथ ही सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा करके सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर टालमटोल करने वाली कांग्रेस ने आखिरकार लालू-तेजस्वी के सामने अपने हथियार डाल दिए। चुनाव में इसका क्या असर होगा यह 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद साफ हो जाएगा।

वही दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए का संकल्प पत्र-2025 जारी कर दिया। इसमें रोजगार, शिक्षा और विकास से जुड़े 25 वादे किए गए हैं। जिनमें, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। हर जिले में फैक्ट्री औद्योगिक पार्क लगाने की योजना, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, मिशन करोड़पति भी शुरू करेंगे, महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता, गरीबों को 125 यूनिट बिजली फ्री, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि में केंद्र 6 हजार दे रही, बिहार की एनडीए सरकार 3 हजार टॉपअप के तौर पर सहयोग करेगी। इस तरह से किसानों को अब 6 के बजाए 9 हजार रुपए मिलेंगे, एनडीए सरकार ने जुब्बा सहनी मतस्य पालक योजना लाने का भी वादा किया। इसके तहत साढ़े चार हजार बिहार और साढ़े चार हजार केंद्र सरकार देगी। मछली पालकों को इस तरह 9 हजार रुपए मिलेंगे, मिथिलांचल में सीतापुरम तो पटना को न्यू पटना ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा, एक्सप्रेस वे और रेलवे से बिहार को मिलेगी और रफ्तार। चार शहरों को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों को बिहार गति शक्ति योजना में लेंगे, दलितों, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाएगा, गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी। एनडीए का संकल्प पत्र-2025 को जारी करते हुए इस अवसर पर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई दिग्गज उपस्थित थे।

बहरहाल, एनडीए और महागठबंधन दोनो ने ही चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। चुनावी मैदान में रैलियों और प्रचार का दौर भी तेज है। नेताओं के हैलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट आसमान में दिखाई-सुनाई दे रहे हैं। एनडीए, महागठबंधन के साथ-साथ जनसुराज और राजद से अलग होकर तेजप्रताप की जनशक्ति जनता दल जनता के बीच विरोधियों को पटखनी देने की कड़ी मशक्कत कर रहे हैं किन्तु मुख्य रूप से बिहार की 51 विधानसभा सीटों पर

भाजपा और राजद के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। भाजपा 101 तथा राजद 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस तरह देखें तो भाजपा की सर्वाधिक सीटों पर लड़ाई राजद से होगी। वहीं, शेष 50 सीटों पर भाजपा की टक्कर कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य घटक दलों से है। राजद की 143 कुल सीटों में 51 पर भाजपा से लड़ाई है। इस तरह राजद के 91 सीटों पर लड़ाई एनडीए के अन्य घटकदलों जदयू, लोजपा (आर), हम और वीआईपी से है। इन्हीं 51 सीटों में ही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी क्षेत्र शामिल है। इन दोनों की सीटों क्रमशः तारापुर और राघोपुर में भी भाजपा और राजद के बीच लड़ाई है। भाजपा के दोनों पूर्व सांसद दानापुर से रामकृपाल यादव और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू की लड़ाई भी राजद प्रत्याशियों से है। राज्य की जिन 51 सीटों पर भाजपा और राजद के बीच लड़ाई है, उनमें मधुबन, मोतिहारी, ढाका, परिहार, सीतामढ़ी, खजौली, बिस्फी, राजनगर (अजा), छातापुर, नरपतगंज, प्राणपुर, केवटी, कुढ़नी, साहेबगंज, बैकुंठपुर, सीवान, गोरियाकोठी, तरैया, अमनौर, हाजीपुर, लालगंज, पातेपुर (अजा), मोहिउद्दीनगर, कटोरिया, तारापुर, मुंगेर, बांकीपुर, दानापुर, बड़हरा, गुरुआ, वारिसलीगंज, जमुई, अलीनगर, बनियापुर, छपरा, सोनपुर, बाढ़, शाहपुर, रामनगर (अजा), नरकटियागंज, हरसिद्धि (अजा), कल्याणपुर, चिरैया, कोचाधामन, बायसी, राघोपुर, पीरपैंती (अजा), रामगढ़, मोहनियां, भभुआ और गोह शामिल हैं। राजद और भाजपा ही ऐसे दो दल हैं, जिनको वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें मिली थीं। राजद को 75 और भाजपा को 74 सीटें प्राप्त हुई थीं। इस बार इन 51 सीटों में कौन कितनी सीटें जीतेगा यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। मगर इतना तय है कि इन सीटों पर सबकी नजरें होंगी।

बिडम्बना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन की सीटों पर सेंध लगाने के लिए बीते वर्ष से ही जनसुराज पार्टी का निर्माण कर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं और इस चुनाव में उन्होंने 116 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है।

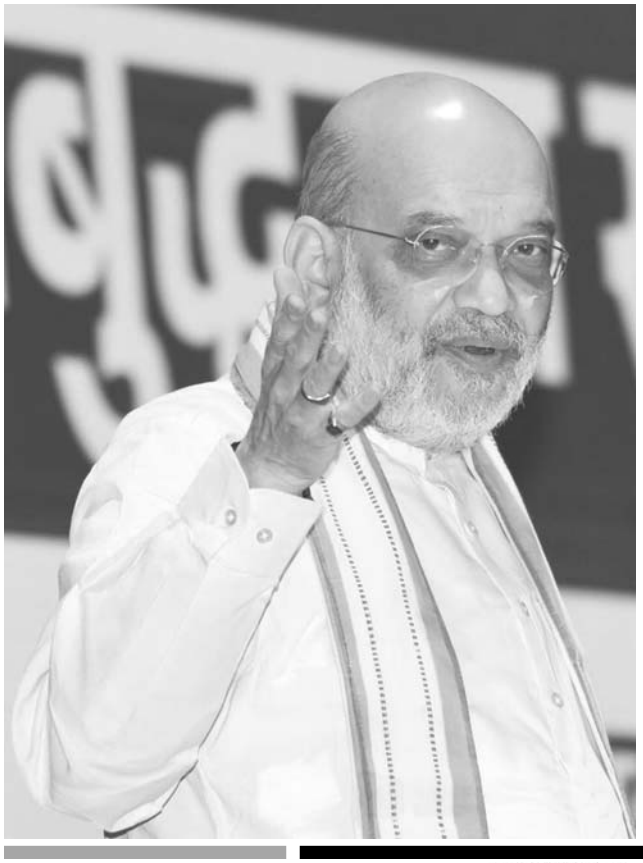

पीके की लोकप्रियता कम समय में इतनी बढ़ी की एनडीए और महागठबंधन दोनो के लिए चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी होंगे। इस दरम्यान जनसुराज पार्टी के भीतर ऐसी घटना घटी जो सूरत कांड जैसी दिखने लगी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीके ने कहा कि बिहार चुनाव में सूरत जैसा कांड रिपीट हुआ है। जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत में भाजपा ने सभी विरोधी कैंडिडेट को बैठा दिया था, उसी तरह बिहार में 3 सीटों पर जन सुराज के कैंडिडेट पर दबाव बनाकर चुनाव लड़ने से रोका गया। उन्होंने कहा कि दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर सीट पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य भाजपा नेताओं ने दबाव बनाकर जन सुराज के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने या नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर किया। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरेआम जन सुराज के प्रत्याशियों को धमकी देकर उन्हें घर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दानापुर से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर साव के अगवा होने की खबर आई थी। मगर, उन्हें किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि अमित शाह और भाजपा के नेताओं ने मुटुर साव को धमकाकर नामांकन करने से रोक दिया। पीके ने मुटुर की गृह मंत्री से मुलाकात का फोटो भी मीडिया को दिखाया।

इसी तरह, प्रशांत किशोर ने बक्सर जिले की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. सत्यप्रकाश तिवारी पर भी भाजपा नेताओं द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीके ने तिवारी के घर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग का फोटो दिखाया। बता दें कि सत्यप्रकाश तिवारी ने ब्रह्मपुर सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया था। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि गोपालगंज विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी ने बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा पर भी भाजपा के एक स्थानीय एमएलसी और अन्य नेताओं ने दबाव बनाया। दो दिन पहले तक वे जन सुराज के लिए प्रचार कर रहे थे, मगर नामांकन वापस ले लिया और फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद भाजपा ने उनकी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की फोटो जारी की थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो गुजरात के सूरत में हुआ था, वही बिहार चुनाव में रिपीट हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेताओं पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। पीके ने वाल्मीकिनगर सीट से जन सुराज के प्रत्याशी दृग नारायण प्रसाद पर भी जदयू के स्थानीय नेताओं द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जब नेता ही मैदान छोड़ दे, तो उनके कार्यकर्ता कितनी देर मैदान में टिकेंगे। प्रशांत किशोर खुद ही चुनाव से पहले ही भाग गए हैं। इसलिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार भी अब मैदान छोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत

किशोर किस दबाव में चुनाव नहीं लड़े। उन पर कौन सा दबाव था, उन्हें बताना चाहिए। वह मैदान छोड़ें तो सही, जब उनकी पार्टी के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं तो वह हम पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्वकर्ता में क्षमता होती है तो वह चुनाव लड़ता है। नेता मैदान में होता है तो उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह रहता है। नेता के मैदान छोड़ने से कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं, तभी तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है। जब, नेता ही भाग जाएगा तो कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे रहेगा?

लब्बोलुआब है कि बिहार की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित मोड़ों और जातिगत समीकरणों की रणभूमि रही है। आगामी विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को होंगे। यह चुनाव न केवल सत्ता की कुर्सी पर दांव लगाने वाला है, बल्कि कई प्रमुख नेताओं के राजनीतिक करियर का भी अंतिम अध्याय लिख सकता है। मोदी मैजिक, नीतीश कुमार की लंबी पारी का समापन, तेजस्वी यादव की उभरती ताकत, राहुल गांधी की राष्ट्रीय अपील और प्रशांत किशोर का 'डार्क हॉर्स' होना, ये सब मिलकर एक रोमांचक ड्रामा रच रहे हैं। यहां महागठबंधन में कांग्रेस और एनडीए में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (आर) अपनी हिस्सेदारी तलाश रही हैं, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी एक नए विकल्प के रूप में उभर रही है। बिहार चुनाव इस मायने में पहले विधानसभा चुनाव भी होंगे, जब चुनाव आयोग ने इस साल 24 जून को बिहार से शुरू होकर देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का फैसला किया। बिहार एसआईआर के बाद, राज्य की मतदाता सूची में 68.5 लाख मतदाताओं की छंटनी की गई, साथ ही 21.53 लाख नए जोड़े गए, जिससे कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ हो गई है। ऐसे में 5 प्रमुख कारक हैं जो बिहार के 243 सीटों वाले इस चुनाव को परिभाषित करेंगे। ये मुद्दे न केवल वोटरों की भावनाओं को प्रभावित करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी बदल सकते हैं। इनमें पहले बिहार की राजनीति में 'नीतीश मॉडल' का नाम अनिवार्य रूप से जुड़ा है, लेकिन 74 वर्षीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रहीं अटकलें इस चुनाव का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन चुकी हैं। विपक्ष, खासकर राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने इसे हथियार बना लिया है। तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंचों पर नीतीश के वीडियो शेयर कर दावा करते हैं कि राज्य अब सात-आठ नेताओं और नौकरशाहों के एक छोटे गुट के हवाले है। कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं के बयान कि 'नीतीश को अब आराम करना चाहिए', इस भावना को प्रतिबिंबित करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से, यह मुद्दा एनडीए के लिए दुधारी तलवार साबित हो रहा है। जेडीयू इन आरोपों को खारिज तो कर रही है, लेकिन सहयोगी 'भाजपा का मौन' कई सवालों को जन्म दे रहा है। भाजपा का कहना है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? संदेह पैदा करता है। यदि नीतीश के स्वास्थ्य का मुद्दा हावी हो गया, तो एनडीए का वोट बैंक, विशेषकर ईबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिखर सकता है। विपक्ष इसे 'परिवर्तन की पुकार' के रूप में पेश कर रहा है, जो युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। कुल मिलाकर, यह मुद्दा नीतीश के व्यक्तिगत करियर से ज्यादा एनडीए की एकजुटता को परखेगा।

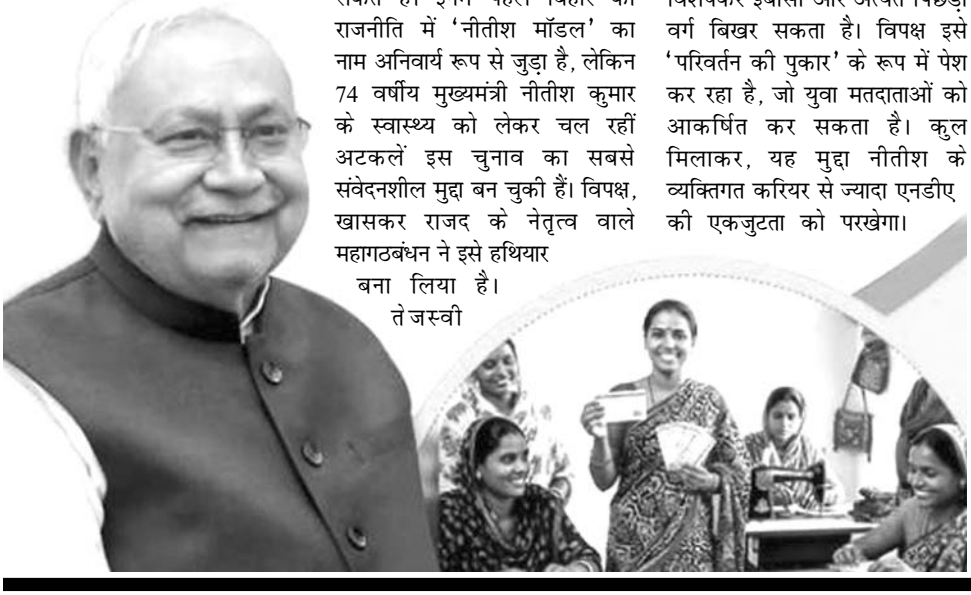

दूसरा यह कि बिहार जैसे गरीबी और बेरोजगारी से जूझते राज्य में वादे हमेशा वोटों का सबसे बड़ा हथियार रहे हैं। एनडीए सरकार ने सत्ता-विरोधी लहर को कुचलने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बाढ़ ला दी है। राज्य की लाखों महिलाओं को 10,000 रुपए का व्यावसायिक अनुदान, 1.89 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए मासिक, जीविका-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और 18-25 वर्ष के बेरोजगारों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ता ये घोषणाएं ग्रामीण और महिला मतदाताओं को सीधे लक्षित करती हैं। ये वादे एनडीए की रणनीति का हिस्सा हैं जो 'मोदी की गारंटी' को बिहार की जमीन पर उतारते हैं। लेकिन विपक्ष इन्हें चुनावी जुमला बताकर खारिज कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि ये योजनाएं कागजी हैं। महागठबंधन अपनी 'न्याय योजना' से पलटवार कर सकता है, लेकिन एनडीए की योजनाओं की तात्कालिक अपील अधिक मजबूत लग रही है। यदि ये योजनाएं वोटों में तब्दील हुई, तो एनडीए को फायदा होगा, अन्यथा दांव उल्टा भी पड़ सकता है। यह मुद्दा बिहार की 'कल्याणकारी राजनीति' को और गहरा करेगा, जहां वोटर अल्पकालिक लाभ पर लॉन्ग-टर्म सुशासन को तरजीह दे सकते हैं। तीसरी बात यह रही कि चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन अभियान को विपक्ष

ने 'वोट चोरी' का हथियार बता दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' में लाखों की भीड़ जुड़ना इस मुद्दे की गंभीरता दर्शाता है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार मतदाता सूची में हेरफेर कर एनडीए के पक्ष में धांधली कर रही है। दूसरी ओर, एनडीए का कहना है कि महागठबंधन 'घुसपैठियों' को वोटर बनाकर साजिश रच रहा है। आंकड़ों के लिहाज से, भले ही चुनाव आयोग के आंकड़े दोनों दावों को कमजोर करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप एसआईआर का मुद्दा ध्रुवीकरण का माध्यम बनेगा। विपक्ष इसे अल्पसंख्यक और गरीब वोटरों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि एनडीए हिंदुत्व के एजेंडे से पलायन रोकने का दावा करेगा। बिहार के संवेदनशील सामाजिक ताने-बाने में यह विवाद जातिगत गठजोड़ों को प्रभावित कर सकता है, खासकर मुस्लिम-यादव समीकरण को। अंततः, यह मुद्दा लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा और राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित करेगा। चौथी बात फेस वेल्यू की है। मोदी बनाम राहुल का राष्ट्रीय मुकाबला। नीतीश कुमार एनडीए का आधिकारिक चेहरा हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी की रैलियां और अपील बिहार के हिंदुत्व-समर्थक वोटरों को एकजुट करती हैं, जबकि स्थानीय भाजपा के चेहरे जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल में राज्यव्यापी प्रभाव कम है। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी अभियान की कमान संभाल रहे हैं, जो उनकी 'वोटर अधिकार यात्रा' की भीड़ को वोटों में बदलने की कोशिश करेंगे। यह मुकाबला बिहार को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना देगा। इसमें मोदी की अजेय छवि बनाम राहुल की उभरती युवा अपील प्रमुख भूमिका निभाएगी। मोदी की छवि का फायदा उच्च जातियों और शहरी वोटरों से होगा, जबकि राहुल दलित-मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत कर सकते हैं। यदि तेजस्वी यादव स्थानीय मुद्दों पर फोकस रखें तो महागठबंधन को संतुलन मिलेगा अन्यथा मोदी फैक्टर एनडीए को बहुमत दिला सकता है। यह चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी ट्रेलर साबित हो सकता है। पांचवा मुद्दा पीके फैक्टर का है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार की जाति-केंद्रित राजनीति में एक ताजा हवा का झोंका है। पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और सुशासन पर फोकस करते हुए किशोर युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं। एनडीए के वादों की बौछार को भी पीके के दावों का जवाब माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से, जेएसपी एक 'थर्ड फोर्स' के रूप में उभर सकती है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काटेगी। बिहार के 40% युवा मतदाता, जो जाति से ऊब चुके हैं, पीके के बदलाव संदेश से जुड़ सकते हैं। यदि जेएसपी 20-30 सीटें जीत ली तो यह किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है। लेकिन, चुनौती यह है कि बिना मजबूत संगठन के यह 'फ्लैश इन द पैन' साबित हो सकती

है। पीके फैक्टर बिहार को 'पोस्ट-जाति' राजनीति की ओर धकेल सकता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल बनेगा।

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने चुन-चुनकर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो कि एनडीए और महागठबंधन के दलों को अच्छी खासी टेंशन दे रहे हैं। हालांकि चुनाव लोगों की जमीनी उम्मीदों पर ही टिका रहता है। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी हटाने, रोजगार, शिक्षा और पलायन को रोकने का वादा करके लोगों को भरोसा दिलाने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी है। अब चुनाव में देखना है कि लोगों को उनके वादे पर कितना ऐतबार होता है। जेएसपी ने पूर्व आईएएस, आईपीएस, वकील, गणितज्ञ और वैज्ञानिकों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। जेएसपी का किसी भी जाति में आधार नहीं है। प्रशांत किशोर ऐसे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं जहां हर पार्टी का एक वोट बेस है और किसी ना किसी जाति से जुड़ी है। प्रशांत किशोर के पटना ऑफिस में भीड़-भाड़ जरूर रहती है लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे उन्हें इतनी सीटें हासिल हों कि वह बिहार के किंगमेकर बन पाएं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव 2025 सत्ता से ज्यादा नेतृत्व और दिशा का चुनाव होगा। नीतीश का स्वास्थ्य, वादों की होड़, वोटिंग प्रक्रिया का विवाद, मोदी-राहुल का मुकाबला और पीके का उदय ये पांच कारक मिलकर बिहार में एक 'जटिल पजल' रचेंगे। एनडीए की मजबूत मशीनरी और मोदी की अपील इसे फेवरेट बनाती है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता और युवा असंतोष उलटफेर भी कर सकता है।

बहरहाल, बिहार चुनाव में सभी राजनीतिक दल पौने दो करोड़ युवा वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे है। बिहार के कुल 7 करोड़, 43 लाख 55 हजार 976 वोटर्स में 20-29 आयु वर्ग के मतदाता एक करोड़ 63 लाख 25 हजार 614 है। वहीं 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 14 लाख एक हजार 150 हैं। इसमें 18-19 आयु वर्ग की महिला मतदाता 5,84,115 हैं। इस प्रकार युवा मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 77 लाख 26 हजार 879 है। ऐसे में चुनाव में यूथ फैक्टर्स को साधने के लिए महागठबंधन और एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। हर घर सरकारी नौकरी का चुनावी दांव-बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए हर घर में सरकारी नौकरी का दांव चला है। तेजस्वी यादव अपने चुनावी मंच पर बिहार मे इस बार युवा सरकार बनाने का दावा करते है। तेजस्वी यादव कहते है कि सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिन परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दांव चला

था और इसका उन्हें फायदा भी हुआ था। तेजस्वी यादव कहते है कि बिहार में 17 महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने पांच लाख युवाओं को नौकरी दी। इसके साथ महागठबंधन ने वादा किया है कि सवा करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन किया जाएगा, इसके साथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को प्रतिमाह 2 हजार और 3 हजार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क समाप्त किया जाएगा। सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु न्यूनतम स्टाइपेंड सुनिश्चित किया जाएगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र में राज्य की सभी जीविका दीदियों को स्थायी करने का वादा किया गया है और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही गई है। जीविका दीदियों का उनका वेतन भी 30 हजार करने का वादा किया गया है। सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने का वादा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 मासिक पेंशन दी जाएगी। हर साल 200 की वृद्ध की जाएगी। दिव्यांगजनों को 3000 मासिक पेंशन की जाएगी। वही बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही जिस तरह से सरकारी नौकरी का चुनावी दांव चला है वह क्या बिहार चुनाव मे गेमचेंजर साबित होगा? बिहार चुनाव को लेकर एक सर्वे में तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी वाले वायदे पर 38.1 फीसदी लोगों ने इसे अच्छा कदम बताया है वहीं 48 फीसदी लोगों ने इसे महज एक चुनावी वादा बताया है।

विदित हो कि बिहार की राजनीतिक मिट्टी में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें उखाड़ना किसी क्रांति से कम नहीं। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जन्मी यह राजनीतिक जोड़ी, आपातकाल के खिलाफ लड़ते हुए समाजवादी सपनों को साकार करने का दावा कर रही थी। पांच दशक बाद, 77 वर्षीय लालू और 74 वर्षीय नीतीश की थकान भरी आंखें बता रही हैं कि यह दौर अब आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है या यह सिर्फ पुरानी किताब का अंतिम पन्ना है? यह दो व्यक्तियों का पतन नहीं, बल्कि एक पूरे युग का अंत है। लालू का राजद यादवों का किला बना रहा, जहां सामाजिक न्याय का नारा पिछड़ों को लामबंद करता रहा। नीतीश का जनता दल (यूनाइटेड) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की आवाज बन गया, जो 2023 के जातिगत सर्वे के मुताबिक

बिहार की 36 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों ने कभी साथ मिलकर, कभी एक-दूसरे को ललकारते हुए बिहार को आकार दिया। बीच में रामविलास पासवान ने दलित-पिछड़े गठजोड़ को मजबूती दी, लेकिन 2020 में उनका निधन इस त्रयी को अधूरा छोड़ गया। अब, बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं ने इन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। नीतीश भले मुख्यमंत्री बने हुए हैं और चुनाव अभियान पर भी निकले हैं, लेकिन उनके बिखरे बयान और आचरण सवाल खड़े करते हैं। लालू की कमान बेटे तेजस्वी ने संभाली है, लेकिन परिवारिक कलह (तेज प्रताप का अलगाव) ने उत्तराधिकार को और जटिल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी इस पुराने दौर को नेस्तनाबूद करने की नई रणनीति बुन रही है। भाजपा की रणनीति साफ है-हिंदू एकीकरण से जाति की दीवारें तोड़ना, ओबीसी-ईबीसी को टिकट और लाभ देकर लुभाना और बिहार को 'विकसित भारत' का हिस्सा बनाना। यहां मोदी-शाह का फैक्टर निर्णायक है। मोदी ने एनडीए के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। एक ऐसा कदम जो ईबीसी-ओबीसी को सीधा निशाना बनाता है, नीतीश के वोटबैंक को चुराने की कोशिश। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का दावा है कि 'लोगों ने मन बना लिया है, एनडीए सरकार ही बनेगी।' लेकिन नीतीश को 'जोखिम' मानते हुए भी उन्हें अलग करने का साहस नहीं जुटा पा रही है भाजपा। नीतीश के बिना एनडीए कमजोर है और उनके साथ पुराना बोझ। बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधनों की बाजीगरी रही है। नीतीश का 'उल्टा-पुल्टा' गठबंधन बाहरी नजरों में अवसरवाद लगता है, लेकिन ईबीसी के लिए जीवट का प्रतीक। उन्होंने यादव प्रधान राजद के खिलाफ बाकी पिछड़ों को एकजुट रखा। लेकिन अब खालीपन साफ है। आज राहुल-तेजस्वी की संयुक्त रैलियां महागठबंधन को गति दे रही हैं। तेजस्वी ने जीविका दीदियों को 30 हजार सैलरी का वादा किया है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बांट सकती है, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज युवा असंतोष भुनाने को तैयार है। इस संक्रमण का सबसे बड़ा सवाल है बिहार में मंडल के बाद की राजनीति कैसी होगी? लालू-नीतीश युग जाति की राजनीति का प्रतीक था। लेकिन अब, भाजपा राम मंदिर से लेकर लोक कल्याण तक जाति को तोड़ रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस सामाजिक न्याय के उत्साह से पिछड़ों को लुभा रही है, तेजस्वी युवा चेहरों से राजद को पुनर्जीवित कर रहे हैं। बिना दिग्गजों के पार्टियां बिखर सकती हैं और ईबीसी वोट ढीला पड़ेगा, नई पीढ़ी विकास-रोजगार पर सवाल उठाएगी। जन सुराज अगर जाति से ऊपर उठी, तो क्रांति संभव है। बिहार को पुरानी स्मृतियों से बाहर निकलना होगा। लालू-नीतीश का दौर गरीबी-भ्रष्टाचार-जातिवाद का आईना था, लेकिन पिछड़ों को आवाज दी। अब समय है जाति-आधारित राजनीति से आगे बढ़ने का। शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग पर फोकस करने का। क्या तेजस्वी नीतीश के 'उलटे-पुलटे' को दोहराएंगे? इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बिहार नया जन्म लेगा या जंजीरों में जकड़ा रहेगा। अंत में, बिहार के 7.4 करोड़ मतदाता तय करेंगे कि राज्य 'परिवर्तन' की राह पर चलेगा या 'स्थिरता' की। यह चुनाव न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारत की राजनीतिक धारा को प्रभावित करेगा। क्या नीतीश की आखिरी पारी शानदार होगी या तेजस्वी का सूरज उगेगा? यह समय ही बताएगा। बस इस चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों को देखकर एक बात कही जा सकती है-'शिक्षा, पलायन और रोजगार, आखिरी पारी-आखिरी दाव'! ●

Namaz at Pune's Shaniwar Wada Sparks Political Controversy;

BJP MP 'Purifies' Fort With Cow Urine

A video showing Muslim women offering Namaz at the historic Shaniwar Wada fort in Pune has triggered a political row, with BJP MP Medha Kulkarni conducting a "purification ceremony" using cow urine and holding a protest against what she called an "outrageous" act. On October 19, Kulkarni shared the viral video on social media, stating, "Shaniwar Wada will not hold namaz recitation, the Hindu community has awakened!". She urged supporters to assemble at the iconic fort, asking, "Historical heritage site or non-Hindu prayer site?" In another post later in the day, Kulkarni described the incident as "extremely outrageous", emphasizing the fort's historical significance as a witness to the Maratha Empire's golden era. She said, "A demonstration was organized on behalf of the entire Hindu community to condemn this incident and demand action against those attempting to disrupt Pune's social harmony." Kulkarni further stressed the importance of unity among Hindus, stating that it is their duty to protect Hindu culture, traditions, and history. Maharashtra Minister Nitesh Rane also condemned the act, highlighting the fort's historical and cultural importance. He remarked, "Shaniwar Wada is a symbol of bravery and holds significance for the Hindu community. If Hindus recite Hanuman Chalisa outside Haji Ali, will it be fine?"

एडीजीपी ने क्यों की आत्महत्या?

हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान में हैं। वाई पूरन कुमार का परिवार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में रहता है। मीडिया खबरों के अनुसार वाई. पूरण कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या की है। उन्होंने अपने गनमैन से बंदूक ली थी। वाई पूरन कुमार हरियाणा पुलिस में 2001 बैच के अफसर थे। 29 सितंबर को ही उनकी पोस्टिंग रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC) में IG के तौर पर हुई थी। बताया जा रहा है कि वह 7 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे। हालांकि हरियाणा पुलिस से उनकी छुट्टी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। पूरन कुमार के गोली मारकर आत्महत्या कर लेने के बाद से

प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिस वक्त उन्होंने आत्महत्या की उस वक्त उनकी पत्नी भी घर पर मौजूद नहीं थी। पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी हैं और इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर गई हुई थी।

मीडिया खबरों के मुताबिक 9 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया गया है। वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की कोठी नंबर 116 में अपनी पत्नी अमनीत पी. कुमार और एक बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी नागरिक उड्डयन विभाग की सचिव हैं। इनकी छोटी बेटी चंडीगढ़ में ही पढ़ाई कर रही है, जबकि बड़ी बेटी विदेश में स्टडी करने के लिए गई हुई है। मीडिया खबरों के मुताबिक चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार पुलिस को मौके से एक वसीयत और एक फाइनल नोट बरामद हुआ है। इन्हें बाकी सबूतों के साथ जब्त कर लिया गया। वाई पूरन कुमार की पत्नी के 8 अक्टूबर को जापान से लौटने के बाद मेडिकल बोर्ड बनाकर पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। मीडिया मौके से मिले नोट में हरियाणा के एक मौजूदा IPS अफसर और 2 रिटायर्ड IPS अफसरों का नाम है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये अफसर कौन है अब तक

इसका खुलासा नहीं हो सका है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। पुरे मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। हालांकि, मीडिया से कुछ भी बताने से बच रही है। अहम बात है कि हाल ही में एडीजीपी वाई पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ रोहतक में एक केस भी दर्ज किया गया था। हालांकि, एसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर ने नोट मिलने की पुष्टि नहीं की, लेकिन साथ ही इंकार भी नहीं किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम भी नोट में लिखा है। वाई पूरण कुमार के रोहतक रेंज आईजी रहते हुए रहे रीडर पर मामला दर्ज हुआ था। शराब कारोबारी से पैसे मांगने के आरोप में यह केस दर्ज हुआ था और वाई पूरण कुमार को आशंका थी कि उन्हें भी फंसाया जा सकता है।

बता दें कि पूरन सिंह बीते चार साल से कई बार सुर्खियों में रहे थे और उन्होंने डीजीपी से लेकर कई अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोला था। रोहतक रेंज के IG रहे वाई पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ दर्ज करप्शन का केस में गनमैन सुशील कुमार ने पुलिस हिरासत में कबूल किया कि वाई पूरन कुमार के कहने पर उन्होंने मंथली मांगी थी। 2 दिन पहले रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में एक FIR दर्ज की गई। रोहतक पुलिस के मुताबिक वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने एक शराब कारोबारी से दो से ढाई लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ी एक ऑडियो क्लिप मिलने के बाद सुशील को अरेस्ट किया गया। रोहतक पुलिस ने सुशील को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गौरतलब है कि बीते चार साल में पूरन सिंह ने कई बार सुर्खियां बटोरीं। वह अपने ही डीजीपी से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक की शिकायत कर चुके थे। साथ थी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी पर जाति के आधार पर ट्रांसफर करने के भी आरोप लगाए थे। साथ ही कुछ आईपीएस अफसरों की प्रमोशन पर भी सवाल उठाए थे। एडीजीपी पूरन कुमार को 29 सितंबर को सरकार ने रोहतक रेंज के IG पद से हटाते हुए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC), सुनारिया में IG लगा दिया था। पुलिस महकमे में इसे एक तरह की पनीशमेंट ट्रांसफर समझा जा रहा था। हालांकि, उन्होंने अब तक ज्वाइनिंग

FINAL NOTE

dated : 07.10.2025

Subject :- Continued blatant Caste based discrimination, targeted mental harassment, public humiliation and atrocities by concerned senior officers of Haryana, since August 2020 which is now unbearable

Primarily all that I expected and requested vide various representations and complaints was equity of treatment as an IPS officer of Haryana Cadre with regard to certain specific issues like application of PPR rules for places of worship to all IPS officers uniformly, timely sanction of earned leave, allocation of official vehicle as per entitlement, official accommodation as per standing order of DGP office, application of MHA guidelines and rules for promotion and cadre management of IPS officers as per rules and other issues. Instead of addressing the same, all the representations and complaints in this regard were ignored and are being used vindictively and in a revengeful manner against me in a malafide manner.

This is clearly in continuation to the caste-based discrimination, public humiliation, targeted mental harassment and atrocities by Sh Manoj Yadava, IPS (1988 Hry) the then DGP Haryana which started when I visited a temple in a police station in Ambala in the year 2020, which is a matter of record and is in notice of all concerned. The caste-based discrimination, mental harassment, public humiliation and atrocities started by Sh Manoj Yadava the then DGP Haryana continues against me till date by other officers of Haryana Cadre. Sh Rajeev Arora, IAS (retd) the then ACS Home did not even sanction me earned leave on time due to which I could not even visit my father for the last time before his death, this causes me continued immense pain and mental harassment and is an irreparable loss till date. This was also intimated to all concerned in writing, including to the then Chief Secretary of Haryana, but no action was taken.

Sh Yadava's batchmates Sh TVSN Prasad, IAS (retd) the then ACS home a Sh P.K. Agrawal, IPS (retd) the then DGP Haryana continued with the same attitu towards me which is a matter of record and related representations/complaints a in official record and has also been brought to the notice of all concerned in writin

All my complaints and representations are a matter of record and are do mentary proof and evidence of the continued and targeted mental harassme atrocities I had to go through for years together. A detailed meeting was chaired the then Hon'ble Home Minister Shri Anil Vij and attended by Sh TVSN Prasad, I the then ACS Home, and Sh Shatrujeet Kapur, IPS DGP Haryana on 07.11.2(and was also documented vide memo 1468 dated 14.11.2023 of IGP Home Gua Haryana but no action has been taken on most of the issues including ex-post fa sanction of approx. 140 places of worship on Police premises, refixation of effect date of promotion of 2001 batch IPS to 01.01.2015 as was done for 1990 ba IPS, safety and security concerns, etc which are a matter of record. Even Dr M F Kiran, IPS (1996 Hry) ridiculed me in public for being posted on an ex-cadre p

नहीं दी थी और कहा जा रहा है कि उन्हें ज्वाइन करना था। लेकिन उससे पहले ही पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में अपने निजी आवास में खुद को गोली मार ली।

बताते चले कि IPS वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद उनकी पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि आरोपी सशक्त अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। अमनीत का कहना है कि उनके पति के 9 पन्नों के सुसाइड नोट और औपचारिक शिकायत के बावजूद अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। मीडिया खबरों के अनुसार पूरन कुमार के सुसाइड के बाद उनकी पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा DGP और रोहतक SP के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। 4 पन्नों की शिकायत में उन्होंने अधिकारियों पर उनके पति को मानसिक उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पति को जातिसूचक गालियां भी दी जाती थीं। सुसाइड नोट में उन्होंने नौकरी से जुड़ी परेशानी, नाराजगी, मानसिक दबाव और कई विवादों का जिक्र किया हुआ है। हालांकि अभी तक नोट और वसीहतनामे को लेकर आधिकारिक रूप कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चंडीगढ़ पुलिस को घटनास्थल से एक वसीयत भी मिली, जिसमें पूरन कुमार ने सारी संपत्ति अपनी पत्नी अमनीत पी. कुमार के नाम करने की बात लिखी है। मीडिया खबरों के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने आत्महत्या करने से पहले उन्होंने अपने सभी सुरक्षाकर्मियों को परिसर से बाहर जाने के लिए कहा था और फिर वह घर के नीचे बने एक कमरे में गए और कुर्सी पर बैठकर खुद को गोली मार ली।

बहरहाल, हरियाणा में सुसाइड करने वाले एडीजीपी वाई. पूरन कुमार मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने जांच दल को कुमार का लैपटॉप देने से इंकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुमार ने अपना सुसाइड नोट अपने लैपटॉप से ही टाइप किया था। यही कारण है कि इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। माना जा रहा है कि पूरन कुमार के लैपटॉप से जांच दल को उनके सुसाइड से जुड़े कुछ सबूत मिल सकते हैं, जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। परिजनों द्वारा लैपटॉप नहीं देने से फिलहाल जांच अटकी हुई है। साथ ही परिजनों ने कुमार का पोस्टमार्टम कराने से भी इंकार किया था। इससे पहले चंडीगढ़ के डीजीपी ने कहा था कि बिना परिवार की अनुमति के पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। दूसरी ओर, परिवार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत की गिरफ्तारी पर अड़ा हुआ है। वही इस मामले में दर्जनभर पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया

को हटा दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस सुसाइड मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर, उनका दर्द बांटा। मुलाकात के बाद उन्होंने हरियाणा सीएम से कहा कि तमाशा बंद कीजिए और अंतिम संस्कार होने दीजिए। उन्होंने दोषी अफसरों पर कार्रवाई की भी मांग की। राहुल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार जी के परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। इस कारण परिवार के साथ ही पूरन जी की बेटियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार जी के साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा रहा था। वाई पूरन कुमार जी का करियर खत्म करने और उन्हें अपमानित करने के लिए कई अफसर काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित भाई-बहनों को गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हों-सक्षम हों, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है। हमें ये स्वीकार नहीं है। राहुल ने कहा कि नेता विपक्ष के नाते मेरा देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा संदेश है कि आपने पूरन कुमार जी की दोनों बेटियों से जो वादा किया है, उसे पूरा कीजिए। इनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। आप दोषी अफसरों पर कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर डाले जा रहे दबाव को हटाइए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर, उनका दर्द बांटा। ऐसी घटनाएं देश और समाज पर कलंक हैं और इस बात का सबूत हैं कि आज वंचित वर्ग उम्मीद खोता जा रहा है। बीजेपी-आरएसएस की नफरत भरी और मनुवादी सोच ने समाज में ऐसा जहर घोल दिया है, जहां इंसानियत दम तोड़ रही है। गौरतलब है कि राहुल के दौरे से पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। वही IPS ओम प्रकाश सिंह को DGP हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ SIR संवैधानिक या असंवैधानिक?

भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान के अनुसार, कोई भी कानून या नियम जो संविधान के विरुद्ध हो, वह असंवैधानिक माना जाता है। संवैधानिक शब्द का अर्थ है संविधान के अनुसार। कोई भी कानून या नियम जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया हो, वह संवैधानिक माना जाता है। संवैधानिक कानूनों का उद्देश्य संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करना होता है। असंवैधानिक शब्द का अर्थ है संविधान के विरुद्ध। कोई भी कानून या नियम जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो, वह असंवैधानिक माना जाता है। असंवैधानिक कानूनों को न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।

✯ संवैधानिक और असंवैधानिक के बीच का अंतर :- संवैधानिक और असंवैधानिक के बीच का मुख्य अंतर यह है कि संवैधानिक कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं, जबकि असंवैधानिक कानून संविधान के विरुद्ध होते हैं। संवैधानिक कानूनों का उद्देश्य संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करना होता है, जबकि असंवैधानिक कानूनों को न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। संवैधानिक और असंवैधानिक के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं और संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करने का उद्देश्य रखते हैं। असंवैधानिक कानून संविधान के विरुद्ध होते हैं और न्यायालय द्वारा रद्द किए जा सकते हैं।

चुनाव आयोग के संदर्भ में, SIR का मतलब है Special Intensive Revision, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाए जाने वाला एक विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करना होता है।

यह एक प्रकार की रिपोर्ट है जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन के लिए तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का विवरण होता है, जैसे कि मतदान केंद्रों की स्थिति, मतदान प्रक्रिया, और चुनाव परिणामों की घोषणा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन के लिए अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया संवैधानिक है, क्योंकि :-

☞ **चुनाव आयोग की शक्तियां :-** चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 में दी गई शक्तियों के तहत चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन करने का अधिकार है।

☞ चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी का पता लगाने में मदद करता है।

☞ **संवैधानिक प्रावधान :-** स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 और चुनाव आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार होती है, जो इसे संवैधानिक बनाती है।

✯ क्या नागरिकता का निर्धारण करना चुनाव आयोग का काम है?

नहीं, नागरिकता का निर्धारण करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। नागरिकता का निर्धारण करना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता से संबंधित मामलों को निपटाता है। चुनाव आयोग का मुख्य काम चुनाव प्रक्रिया को संचालित करना, मतदाता सूची को अद्यतन करना, और चुनाव से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग को नागरिकता से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

✯ क्यों विरोध हुआ SIR का?

विपक्षी राजनीतिक दल SIR का विरोध इसलिए कर रहे थे कि नागरिकता प्रमाण पत्र में जिन जरूरी दस्तावेजों की मांग की गई है उसमें से आधार कार्ड ,वोटर आई कार्ड, मनरेगा कार्ड को दस्तावेज की सूची में से बाहर रखा गया है और यह मामला भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय निर्वाचन आयोग से तीखे प्रश्न पूछे हैं की ष्आधार कार्ड ,वोटर आई कार्ड, मनरेगा कार्ड को आप क्यों नहीं जरूरी दस्तावेज में शामिल किए हैं और अगर आपको लगता है कि यह तीनों कार्ड बड़ी मात्रा में जाली बनवाए गए हैं तो दुनिया का कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है, आपका काम नागरिकता का निर्धारण करना नहीं है। हालांकि, चुनाव आयोग मतदाता सूची में शामिल होने के लिए नागरिकता के प्रमाण की मांग कर सकती है, लेकिन यह नागरिकता का निर्धारण करने के लिए नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच के लिए है। इसलिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन करने में मदद करती है।

✯ आपराधिक कानून में मेंस रिया एवं मोटिव में क्या अंतर है?

आपराधिक कानून में, मेंस रिया और मोटिव (अर्थात् उद्देश्य) में मुख्य अंतर यह है कि मेंस रिया अपराध के समय व्यक्ति की दोषी मानसिक स्थिति (गिल्टी माइंड) को दर्शाता है, जबकि मोटिव उस कार्य के पीछे का वास्तविक उद्देश्य या कारण होता है, जो हमेशा अपराध साबित करने के लिए जरूरी नहीं होता है।

☞ **मेंस रिया की परिभाषा :-** मेंस रिया लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ 'दोषी मन' होता है। यह वह मानसिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपराध करने का इरादा, जानकारी, या लापरवाही रखता है। किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाता है, जब उसने दोषपूर्ण मानसिकता (मेंस रिया) के साथ अपराध किया हो।

☞ **मोटिव (उद्देश्य) की परिभाषा :-** मोटिव वह कारण या उद्देश्य है, जिसके चलते व्यक्ति कोई कार्य करता है, जैसे कि किसी ने किसी को मार डाला; अगर उसका उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करना था, तो वह मोटिव है। मोटिव अपराध का सबूत है, पर कई बार कानून में इसकी आवश्यकता नहीं होती; मुख्य रूप से कोर्ट आरोपी के इरादे (मेंस रिया) पर ध्यान देती है न कि मकसद पर।

☞ **दोनों में मुख्य अंतर :-**

☞ **मेंस रिया :-** दोषी मन, अपराध करने की मानसिक स्थिति।

☞ **मोटिव :-** कार्य के पीछे का उद्देश्य या कारण।

☞ **कानूनी भूमिका :-**

मेंस रिया अपराध साबित करने के लिए आवश्यक होती है।

मोटिव केवल परिस्थितियों को स्पष्ट करने में सहायक होती है।

☞ **निष्कर्ष :-**

अदालतें अपराधी को सजा देने में मुख्य रूप से मेंस रिया यानी दोषी मानसिकता पर ध्यान देती हैं, न कि केवल उस कार्य के पीछे के उद्देश्य (मोटिव) पर।

अपराध सिद्ध करने में मेंस रिया का प्रासंगिकता अधिक है जबकि मोटिव की भूमिका सहायक है।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यता:-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नात्तक उतीर्ण	स्नात्तक/इंटर	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करे:-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग

पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008